गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 203
दि. 24.11.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

राजनाथ सिंह के 'सिंध वापसी' वाले बयान से उपजा नया राजनीतिक तूफ़ान, इतिहास और भू-राजनीति की गूंज से देश-दुनिया में हलचल

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सर्द शाम में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान जैसे ही मंच से उतरा, दिल्ली से कराची तक राजनीतिक हलकों में अचानक हलचल दौड़ गई। राजनाथ सिंह ने बड़े संयम से मगर गंभीरता के साथ कहा कि सिंध आज भले पाकिस्तान का हिस्सा हो, पर सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से वह हमेशा भारत की आत्मा का एक अंग रहा है। उन्होंने आगे एक ऐसा वाक्य कहा जिसने पूरे विमर्श को नई दिशा दे दी—"कौन जानता है, आने वाले कल में सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए।" इन शब्दों ने केवल एक टिप्पणी का रूप नहीं लिया, बल्कि एक गहरे ऐतिहासिक स्मृति को जगाते हुए राजनीतिक गलियारों में तूफ़ान खड़ा कर दिया।

राजनाथ सिंह ने अपने वक्तव्य में बताया कि सिंध वह भूमि है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता ने पहली बार अपनी सांस्कृतिक रोशनी फैलाई थी, जिसे आज भी मानव इतिहास की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में गिना जाता है। विभाजन के घाव भले ही 75 वर्षों से अधिक पुराने हों, लेकिन सिंधी समुदाय का हृदय अभी भी उसी मिट्टी से बंधा है, जहाँ उनके पूर्वजों ने अपने सपनों को आकार दिया था। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी याद किया, जिनका जन्म कराची में हुआ था और जिन्होंने हमेशा सिंध को केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि भावनात्मक मातृभूमि कहा था। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध के लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वे भारत की सांस्कृतिक चेतना का ही हिस्सा

हैं और रहेंगे।

सम्मेलन के मंच पर खड़े होकर रक्षा मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के पक्ष में अपनी बात भी उसी दृढ़ता से रखी। उनका कहना था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वर्षों से धार्मिक अल्पसंख्यकों—विशेष रूप से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय—को प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति में उलझी पूर्व सरकारें इन पीड़ितों की ओर कभी पूरी संवेदनशीलता से नहीं देख सकीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पीड़ा को समझा जिस दर्द से हजारों परिवार अपनी पहचान और सुरक्षा बचाने के लिए भारत आए। CAA उन लोगों के लिए एक राहत की सांस है, जिन्हें इतिहास ने बेघर बना दिया था।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 का उद्देश्य उन लोगों को भारतीय नागरिकता दिलाना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए। यह कानून उन्हें अवैध प्रवासी मानने की धारणा से मुक्त करता है और उन्हें भारत में सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार प्रदान करता है। राजनाथ सिंह के अनुसार यह कानून मानवता और न्याय की भावना पर आधारित है और उनका मानना था कि भारत अपने किसी भी शरणार्थी की पीड़ा को अनदेखा नहीं कर सकता।

लेकिन राजनाथ सिंह का वह वाक्य—"सिंध वापस भारत आ सकता है"—सिर्फ एक भावनात्मक या सांस्कृतिक संदर्भ भर नहीं था। इसमें एक भू-राजनीतिक इशारा छिपा हुआ था जिसने पूरे दक्षिण एशिया में एक नया राजनीतिक ताप जोड़ दिया। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बयान को तुरंत अपने विमर्श का हिस्सा बना लिया और कई लोगों ने इसे भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत माना। वहीं भारत में विपक्ष ने इस बयान को लेकर राजनाथ सिंह पर राजनीतिक वातावरण गरमाने का आरोप लगाया। जबकि सरकार के समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक पुनर्स्मरण और ऐतिहासिक संदर्भ का स्वाभाविक विस्तार बताया।

राजनीति और कूटनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि सिंध का प्रश्न केवल ज़मीन का नहीं बल्कि सभ्यता की स्मृति का सवाल है। विभाजन ने केवल सीमाएं नहीं खींचीं, उसने लोगों के दिलों को भी दो हिस्सों में बांट दिया था। आज भी लाखों सिंधी परिवार ऐसी परंपराओं, बोली, वेशभूषा और स्मृतियों को समेटे हुए हैं जो सीधे-सीधे सिंध की धरती से जुड़ी हैं। इस समुदाय के लिए सिंध एक भूगोल नहीं, बल्कि भावनाओं का अनन्त संसार है।

राजनाथ सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत-पाकिस्तान संबंध वर्षों से बेहद नाजुक स्थिति में हैं। ऐसे में उनके शब्द कूटनीतिक नज़रिये से भी महत्व रखते हैं। सीमाएं बदलने की संभावना पर चर्चा दक्षिण एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बड़े राजनीतिक संकेत देती है।

यह कहना कठिन है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि राजनाथ सिंह के इस कथन ने इतिहास, राजनीति, संस्कृति और कूटनीति की परतों को एक बार फिर से खंगालने पर मजबूर कर दिया है। यह बयान केवल एक सम्मेलन का हिस्सा नहीं रहा—यह उन स्मृतियों और प्रश्नों को जगाने वाला वक्तव्य बन गया है जो कई दशकों से भारतीय उपमहाद्वीप के मन में मौन पड़े थे। राजनीति में कभी-कभी एक वाक्य वर्षों की बहस को जन्म दे देता है, और राजनाथ सिंह का यह बयान शायद उसी श्रेणी में दर्ज हो चुका है।

सागर की काली शाम—एक ही झटके में चार मासूम खत्म, अनंतपुरा गांव में पसरा मातम

(जीएनएस)। मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में रविवार की शाम अचानक मौत की एक ऐसी आंधी लेकर आई, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रहली थाना क्षेत्र के अनंतपुरा गांव के बाहर सड़क किनारे खड़े चार किशोरों को एक तेज़ रफ्तार बस ने ऐसी बेरहमी से कुचल दिया कि पूरा गांव शोक में डूब गया। सड़क किनारे खड़ी एक बाइक के पास खड़े ये बच्चे भैंसों की तलाश में निकले थे, और शायद उन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले कुछ ही पल उनके जीवन का आख़िरी अध्याय बन जाएंगे। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि चारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और सड़क पर अचानक चीख, भगदड़ और रुलाई भर गई। गांव के लोगों के अनुसार चारों बच्चे दोपहर के बाद भैंसें ढूंढने निकले थे, जैसे रोज़ निकलते थे। वे सड़क किनारे उस पुरानी बाइक के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे, शायद दिनभर की थकान के बीच हंसी-मज़ाक भी चला होगा। उसी समय सिमरिया से दमोह की ओर तेज दौड़ती एक निजी बस वहां पहुँची। कहते हैं कि रफ्तार कभी-कभी ज़िंदगी से बड़ी हो जाती है, और यहां भी वही हुआ। बस चालक को शायद अंदाज़ा ही न रहा होगा कि सड़क किनारे मासूम खड़े हैं। बस सीधे बच्चों पर चढ़ गई। टक्कर ऐसी कि शरीर कई फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरे। आसपास मौजूद लोगों ने चीखकर बस को रोकने

की कोशिश की, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। चार नाबालिगों के खून से सड़क लाल हो चुकी थी और गांव का दिल जैसे उसी क्षण थम गया हो। मरने वालों में शिवम (18) और सत्यम (17) दो सगे भाई थे—दोनों घर की आशा, दोनों परिवार की हिम्मत। तीसरा बच्चा प्रशांत उर्फ़ प्राशू (14) घर का इकलौता बेटा था, जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई थी। चौथा किशोर उमेश (16) दो भाइयों में छोटा था और पढ़ाई के साथ अपने पिता का हाथ बंटाता था। दर्द इस बात से और अधिक बढ़ गया कि एक ही परिवार की नसें जैसे एक साथ कट गईं—माएं रो-रोकर बेहोश हो रही थीं, पिता पत्थर की तरह खड़े रह गए, और गांव की हर आंख में नमक जैसे जम गया हो। प्रशांत की छोटी बहन अपने भाई के जाने का अर्थ भी ठीक से नहीं समझ पा रही, बस रोती जा रही है। शिवम और सत्यम की मां का रो-रोकर बुरा हाल है; उमेश के परिवार में तो जैसे खामोशी चाकू की तरह चुभ रही है। वारदात के तुरंत बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। कोई बच्चों के शव ढक रहा था, कोई सड़क किनारे बैठकर सिर पकड़कर रो रहा था। कुछ लोग बस चालक को कोस रहे थे, कुछ भगवान को। पुलिस रहली थाने से मौके पर पहुंची और बस को कब्ज़े में ले लिया। चालक फरार बताया जा रहा है, पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। चारों शवों को रहली अस्पताल भेजा गया जहां पोस्टमार्टम की तैयारी की गई। अस्पताल से लेकर गांव तक, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था—क्या इतनी जानें सिर्फ तेज़ रफ्तार और लापरवाही के कारण चली जानी चाहिए? शोक की इस लहर ने राजनीतिक गलियारों तक भी दस्तक दी। देवरी विधायक बृजबिहारी पटेरिया मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौटकर सीधे घटनास्थल पहुंचे। उनके चेहरे पर वही स्तब्धता थी जो गांव के हर चेहरे पर थी। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार से हरसंभव आर्थिक सहायता दिलाने की कोशिश होगी। उनका यह कहना भी गांववासियों की पीड़ा को कम नहीं कर सका कि यह घटना हृदय विदारक है। क्योंकि जिन घरों में चूल्हे बुझ चुके थे, वहां सांत्वना भी किसी टूटी हुई तसल्ली जैसी लग रही थी। मृतकों के चाचा भगवानदास घटना याद करते हुए कहते हैं—"चारों बच्चे भैंसें खोजने निकले थे। बाइक के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। हमें लगा था थोड़ी देर में लौट आएंगे। पर अचानक एक धमाका हुआ, और हमारी दुनिया उजड़ गई। सब इतना तेज़ हुआ कि हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया।" अनंतपुरा गांव की गलियों में आज सिर्फ सन्नाटा है। चार-चार अर्थियां एक साथ उठना किसी छोटे गांव के लिए किसी क़यामत से कम नहीं। बच्चों के स्कूल बैग अब घर के एक कोने में पड़े हैं, किताबों के पन्ने जैसे उन आँखों से सवाल पूछते हैं जो अब कभी खुलेंगी नहीं। सड़क अभी भी लाल धब्बों को समेटे है, हवा में अभी भी मातम की नमी है और इस काली शाम की कहानी आने वाले कई वर्षों तक गांव की यादों में जख्म की तरह दर्ज रहेगी।

दुनिया के सामने खुल गई पाकिस्तान की गढ़ी हुई कहानी-राफेल गिराने का दावा बन गया हास्यास्पद झूठ

(जीएनएस)। दक्षिण एशिया की राजनीति में दुष्प्रचार कोई नई बात नहीं, लेकिन कभी-कभी झूठ इस हद तक फैलाया जाता है कि वह खुद अपनी ही परछाई से डरने लगता है। ठीक ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के उस दावे के साथ जिसमें उसने भारत के राफेल विमानों को गिराने का शोर मचाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने तेज, सटीक और बहुआयामी सैन्य कार्रवाई—ऑपरेशन सिंदूर—को अंजाम दिया, तो पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और उसका आंतरिक ढांचा हिल गया। यह अभियान केवल सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि यह पाकिस्तान की पुरानी रणनीति को सीधी चुनौती देने वाला ऑपरेशन था। भारतीय वायुसेना ने सीमापार और LoC के आसपास सौ से अधिक आतंकियों को खत्म किया और छह पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराने की पुष्टि भी की। ऐसे क्षण में पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ी—एक मैदान में और दूसरी अपनी जनता के बीच। जब सेना हारती है तो उसके भीतर बैठे रणनीतिकार अक्सर भाषणों और दावों का किला बनाकर मनोबल बचाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के Geo TV की वह रिपोर्ट इसी मानसिकता का प्रतीक थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि

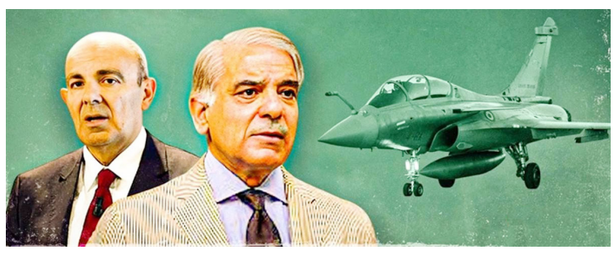

पाकिस्तान ने भारतीय राफेल विमानों को मार गिराया और फ्रांस की नौसेना के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। यह दावा इतना बोल्ड, इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि एक पल के लिए सामान्य दर्शक भी चौंक जाए, पर इसकी नींव वह अफवाह थी जो हकीकत से उतनी ही दूर थी जितनी कराची की रातें चाँद से। Geo TV ने जिस अधिकारी के बयान का हवाला दिया, उसका नाम गलत लिखा गया, उसकी पदवी बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई और उसकी टिप्पणी को पूरी तरह विकृत करके पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कमांडर Jacques Launay नामक अधिकारी ने राफेल गिराए जाने की बात को स्वीकार किया, लेकिन फ्रेंच नेवी ने सारे दावों का परदा एक झटके में फाड़ दिया। असली अधिकारी का नाम Yvan Launay है और उन्होंने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया। उससे भी बड़ा तथ्य यह कि उन्होंने इस विषय पर टिप्पणी ही नहीं की थी क्योंकि वह उनके कार्यक्षेत्र में आता ही नहीं। फ्रांस की नौसेना Marine Nationale ने जब आधिकारिक तौर पर पूरे दावे को फर्जी बताया, तो केवल पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश नहीं हुआ, बल्कि यह बात भी उजागर हो गई कि आज के दौर में झूठ के पैर पहले से कहीं छोटे हो गए हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल मॉनिटरिंग, उपग्रह निगरानी और खुली सूचना व्यवस्था के कारण कोई भी राष्ट्र अपनी हार को छुपाने के लिए मनगढ़ंत दावों की दीवार खड़ी नहीं कर सकता। फ्रेंच नेवी ने Geo TV की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट साझा करके उसे "बहुत गलत और पूरी तरह भ्रामक" बताया और इस तरह वह कहानी, जो पाकिस्तान ने बड़े गर्व से दुनिया को सुनाई थी, ध्वस्त होकर जमीन पर गिर गई। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी कहानी गढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब सरल है—हार का दर्द बहुत बड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए केवल एक सैन्य पराजय नहीं था, बल्कि वह उसकी रणनीतिक सोच, उसके सुरक्षा ढांचे और उसकी वर्षों पुरानी नीति पर चोट था। आतंकियों को संरक्षण देने की उसकी नीति पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लानतें ही पड़ी थीं, पर अब यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत उसकी 'स्ट्रेटेजिक डेप्थ' को भी चुनौती देने लगा है। सौ से अधिक आतंकी ठिकाने तबाह हुए, छह लड़ाकू विमान गिराए गए, और इसी तनाव में पाकिस्तान के अधिकारी और मीडिया जनता को यह भी न बता पाए कि असल नुकसान कितनी दूर तक गया। ऐसे में झूठ ही वह एकमात्र सहारा लगता है जो हार को छुपा सके। परंतु झूठ की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह सत्य के सामने टिक नहीं पाता। फ्रेंच नेवी की एक पोस्ट ने पाकिस्तान के इस दावा-किले को गिरा दिया। और फिर यह स्पष्ट हो गया कि जो राष्ट्र अपनी जनता से ही सत्य को छुपाए, वह दुनिया की निगाह में विश्वसनीयता खो देता है। पाकिस्तान का यह झूठ अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसकी साख को पहले से ज्यादा आहत कर गया और उसे यह भी समझना पड़ा कि सूचना के युग में हवा में लिखी कहानियाँ कुछ ही क्षणों में मिट जाती हैं।

"एनपीएल में छाया सट्टेबाज़ी का साया: काठमांडू में आठ भारतीय गिरफ्तार, क्रिकेट की साख फिर सवालों में"

(जीएनएस)। काठमांडू की ठंडी शाम में अचानक हलचल उस समय बढ़ गई जब क्राइम ब्रांच ने बल्खु क्षेत्र में छापेमारी करते हुए नेपाल प्रीमियर लीग में चल रही सट्टेबाज़ी को लेकर बड़ी कार्रवाई की। क्रिकेट को लेकर उत्साह और रोमांच से भरे इस टूर्नामेंट पर बीते कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे, लेकिन गुरुवार देर रात की इस पुलिस कार्रवाई ने पहली बार यह साफ़ किया कि मैदान की चमक के पीछे एक अंधेरा कारोबार चल रहा था। इस कार्रवाई में आठ भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जो ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिये मैचों के नतीजों पर धन लगा रहे थे। जैसे ही यह खबर फैली, काठमांडू के सियासी और खेल जगत में चर्चा का माहौल बन गया कि आखिर यह नेटवर्क कितने बड़े पैमाने तक फैला हुआ है। काठमांडू क्राइम ब्रांच के एसपी पवन भट्टराई ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर लंबे समय से नज़र रखी जा रही थी और जैसे ही उनकी गतिविधियों के ठोस सबूत मिले, टीम ने देर किए बिना कार्रवाई की। उनकी टीम ने बल्खु में मौजूद एक किराए के फ्लैट में दबिश देकर इन आठों को एक साथ धर दबोचा। पुलिस के अनुसार, ये लोग लंबे समय से नेपाल में रहकर नेटवर्क चला रहे थे और कई ऑनलाइन ग्रुप्स के माध्यम से मैच दर मैच सट्टा लगा रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान भी सामने आ गई है, जिनमें ज्यादातर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से हैं। उनके नाम हैं—31 वर्षीय राजा यदुला, 35 वर्षीय महेश बाबू, 30 वर्षीय पंडित श्रीनिवासुलु, 20 वर्षीय शेख सोयब, 30 वर्षीय नभिन मड्डेला, 32 वर्षीय महमद रफी शेख, 19 वर्षीय साई कुमार तम्मिसेट्टी और 28 वर्षीय शेख चंद बसल। इनकी उम्र भले ही अलग-अलग हो, लेकिन इन सबके बीच की एक समान कड़ी यही थी कि वे क्रिकेट को जुए की मेज तक ले जाने में जुटे हुए थे। पुलिस ने बताया कि इनके पास से 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें कई ग्रुप चैट, कॉल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन और विदेशी नंबरों के संपर्क मिले हैं। भट्टराई के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि ये लोग केवल खुद सट्टा नहीं लगाते थे, बल्कि दूसरों को भी ऐप्स के ज़रिये जोड़ने का काम करते थे, जिससे उनका कमीशन तय होता था। यानी यह सिर्फ मनोरंजन की आड़ में जुआ खेलने का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क था जिसका फोकस सिर्फ लाभ कमाना था—चाहे क्रिकेट की विश्वसनीयता पर कितना भी दाग क्यों न लगे। इस घटना ने एनपीएल की विश्वसनीयता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिन पहले भी दो अन्य लोगों को खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन घटनाओं ने संकेत दिया है कि क्रिकेट के आकर्षण और लोकप्रियता का दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है। नेपाल जैसी उभरती क्रिकेट राष्ट्र में ऐसे मामले न केवल खेल की छवि पर धब्बा हैं, बल्कि आने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के मनोबल को भी झटका देते हैं। काठमांडू में खेल प्रेमियों की चर्चा अब सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि उस छाया की है जो खेल की पवित्रता को निगलने की कोशिश कर रही है। पुलिस का दावा है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होने में अभी और समय लगेगा।

"मस्जिद को राजनीति का मंच बनाने की कोशिशें बढ़ीं, लेकिन सहारनपुर से उठी संयम की आवाज़—इमरान मसूद ने दी सख़्त नसीहत"

(जीएनएस)। सहारनपुर के शांत माहौल में तब हलचल तेज हो गई जब पश्चिम बंगाल की राजनीति से उठी एक बयानबाज़ी उत्तर भारत के सियासी गलियारों में भी गूंजने लगी। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' की नींव रखने की घोषणा ने अचानक पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह बयान एक ऐसे घाव को कुरेदने जैसा माना गया, जिसकी राजनीतिक संवेदनाएँ देश की धड़कनों को दशकों से झकझोरती आई हैं। इसी माहौल में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद आगे आए और उन्होंने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देकर सियासी भाषा में मर्यादा और समाज में शांति का संदेश देने की कोशिश की।

इमरान मसूद ने कहा कि वह इस घोषणा से पूरी तरह असहमत हैं और ऐसी कोई भी पहल, चाहे किसी भी दल या व्यक्ति की हो, समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने की कोशिश बन जाती है। उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा कि मस्जिद की मूल पहचान इबादत है; वह सियासत की प्रयोगशाला नहीं हो सकती। इमरान मसूद की आवाज़ में एक ऐसी बेचैनी झलक रही थी जो समाज के भीतर पनपती नफ़रत को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब हम खुद बार-बार यह आरोप लगाते हैं कि नफ़रत फैलाई जा रही है, तो फिर हमें भी अपने शब्दों और घोषणाओं में ज़िम्मेदारी दिखानी चाहिए। मस्जिद के नाम या तारीख को राजनीतिक नारे में बदलना, उनकी नज़र में, आग में घी डालने जैसा है।

साफ़-सुथरी और ठंडी राजनीतिक भाषा से अलग, मसूद का यह बयान भावनाओं के धरातल पर था—एक ऐसा संदेश जो भीड़ नहीं, समाज को संबोधित करता दिखा। इस विवाद के बीच एक और परत जोड़ते हुए उन्होंने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के हालिया बयान का समर्थन किया। मदनी ने कहा था कि विश्व स्तर पर यह धारणा बन गई है कि मुसलमान कमजोर हो गए हैं, पर भारत में वास्तविकता इससे अलग और अधिक जटिल है। उनके अनुसार, अब भी इस समुदाय के लोगों के लिए देश के शीर्ष पदों तक पहुंचना बेहद कठिन है। इमरान मसूद ने इस पर कहा कि मदनी ने सोच-समझकर, देश की एकता को ध्यान में रखते हुए बात कही है और कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब उसके नागरिकों की तरक्की समान गति से होती है, न कि किसी एक वर्ग के दबाव में।

इन प्रतिक्रियाओं के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक और ट्रैक सामने आया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया। इस पर भी इमरान मसूद ने अपनी आवाज़ तेज़ की और कहा कि जनता को बताया जाए कि अब तक कितने घुसपैठियों की पहचान की गई है और उन्हें कहाँ रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डिटेंशन सेंटरों की चर्चा और घुसपैठ के आँकड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल ज़्यादातर डर की राजनीति को बढ़ावा देता है। मसूद ने एक वार फिर चुभते अंदाज में किया और कहा कि अगर सीमाओं पर सुरक्षा की स्थिति वाकई इतनी चिंताजनक है तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए और पद छोड़ देना चाहिए।

कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम एक ऐसे दौर की निशानी बन गया है जहाँ धार्मिक स्थलों के नाम से शुरू होने वाले बयानों से लेकर डिटेंशन सेंटरों की सरकारी योजनाओं तक, हर चीज़ सियासत का विषय बनती जा रही है।

संपादकीय

दुबई में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना

दुबई एयर शो में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का दुर्घटनाग्रस्त होना इसलिए और अधिक दुखद है, क्योंकि इसमें पायलट की जान भी चली गई। लड़ाकू विमानों के पायलट इसलिए कहीं अधिक कीमती होते हैं, क्योंकि वे गहन प्रशिक्षण के बाद तैयार होते हैं। उनके न रहने से देश कुशल सैनिक के साथ उनकी ओर से अर्जित की गई क्षमता से भी वंचित हो जाता है। हवाई करतब के जरिये अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहा तेजस ऐसे समय दुर्घटना का शिकार हुआ, जब वह दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा था। दुबई एयर शो में विमानन क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों की भागीदारी होती है। यह शो एयरोस्पेस उद्योग के लिए एक ऐसा मंच बन गया है, जहां विमानों की खरीद-बिक्री के सौदे होते हैं।

स्पष्ट है कि ऐसे मंच पर तेजस का दुर्घटनाग्रस्त होना कहीं अधिक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इसे स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना के लिए किसी तरह के आघात की संज्ञा देना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा लड़ाकू विमान नहीं, जो दुर्घटना से दो-चार न होता हो। अति उन्नत माने जाने वाले लड़ाकू विमान भी दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। तथ्य यह भी है कि किसी एयर शो में लड़ाकू विमान के साथ पेश आने वाला यह पहला हादसा नहीं। इसी अगस्त में पोलैंड में आयोजित एयर शो में अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-16 हवाई करतब दिखाते हुए ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके पहले भी कई एफ-16 विमान दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इसकी तुलना में नौ वर्ष पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए तेजस के साथ पेश आया यह दूसरा हादसा है।

चूंकि तेजस अपनी क्षमता सिद्ध कर चुका है, इसीलिए वायुसेना ने उसकी खरीद के बड़े आर्डर दिए हैं। तेजस के चलते भारत की गिनती उन चंद देशों में होने लगी है, जिन्होंने अपने लड़ाकू विमान का निर्माण खुद किया है। वायुसेना ने तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट आफ इन्क्वायरी का जो आदेश दिया, उसके निष्कर्षों को लेकर इस लड़ाकू विमान का निर्माण करने वाली कंपनी एचएएल को भी सजग रहना चाहिए। इस हादसे को एक चुनौती मानकर उससे पार पाने का संकल्प लिया जाना चाहिए।

भारत पहले भी इस तरह की चुनौतियों से पार पा चुका है। जितना आवश्यक यह है कि पर्याप्त संख्या में तेजस लड़ाकू विमान समय रहते तैयार किए जाएं, उतना ही यह भी कि उन्हें और अधिक उन्नत एवं समर्थ बनाने को प्राथमिकता दी जाए। यह कोशिश खास तौर पर होनी चाहिए कि इस लड़ाकू विमान के अधिकाधिक उपकरण स्वदेशी ही हों। सबसे अधिक आवश्यक यह है कि इन विमानों के इंजन के लिए अमेरिका पर निर्भरता खत्म की जाए। ऐसा होने पर तेजस के लिए विश्व बाजार में स्थान बना लेना भी आसान हो जाएगा।

तमिल राजनीति और केंद्र-राज्य टकराव

"राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए पहले इसी अदालत द्वारा निर्धारित अपनी ही समय-सीमा वापस जरूर ले ली, पर असाधारण स्थितियों में राज्यों के लिए अदालत का दरवाजा भी खुला रहने दिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय कार्यपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 20 नवंबर को राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए पहले इसी अदालत द्वारा निर्धारित अपनी ही समय-सीमा वापस ज़रूर ले ली, पर असाधारण स्थितियों में राज्यों के लिए अदालत का दरवाज़ा भी खुला रहने दिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायालय कार्यपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा है जब कोई राज्यपाल कानून बनाने की प्रक्रिया में 'लंबी, अस्पष्ट और अनिश्चित' देरी का कारण बने, तब राज्य सरकार अदालत की शरण ले सकती है। इस तरह से अदालत ने केंद्र और राज्यों के बीच एक जटिल राजनीतिक मुद्दे में नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की है। अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 8 अप्रैल के फैसले के कारण तमिलनाडु के जिन 10 कानूनों पर राज्यपाल की स्वीकृति मान ली गई थी, उनकी स्थिति क्या होगी। कुछ संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि वे कानून बन चुके हैं और उनकी अधिसूचना गजट में भी हो चुकी है, इसलिए उन्हें स्वीकृत मान लेना चाहिए।

दशकों से देश राज्यपालों की भूमिका को लेकर विमर्श कर रहा है, पर रास्ता अभी तक नहीं निकला है। हां, इतना जरूर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई मामले में फैसले के बाद राज्यों में सरकारों की बर्खास्तगी का चलन खत्म हो गया और सरकारों के बनने-बिगड़ने का स्वीकृत सिद्धांत बन गया। अप्रैल में न्यायिक-हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ था, जब गैर-भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच तनाव चरम पर था। खासतौर से तमिलनाडु में एमके स्टालिन की डीएमके सरकार भाषा तथा मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह

प्रवेश परीक्षा 'नीट' से छूट को लेकर केंद्र सरकार के साथ टकराव की मुद्रा में थी। इस मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार 2023 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी है। गत 15 नवंबर को उन्होंने एक और याचिका दायर की है।

इन बातों को अगले छह महीनों में होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव की पूर्व-पीठिका के रूप में भी देखना चाहिए। देश में शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। इसे लेकर कई तरह के टकराव हैं। पिछले कुछ समय से तमिलनाडु सरकार ने तीन भाषा सूत्र, चुनाव-क्षेत्र परिसीमन और 'नीट' जैसे मसलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन मामलों के कारण राजनीतिक-कोलाहल तो हुआ है, पर बुनियादी तौर पर कुछ हुआ नहीं है।

इस साल अप्रैल में, उच्चतम न्यायालय के दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने राज्यपालों के लिए लंबित विधेयकों पर कार्रवाई करने हेतु एक समय-सीमा निर्धारित की थी। अदालत ने पहली बार यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा विचारार्थ रखे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय करें। यह निर्णय इस बात की स्वीकृति थी कि, हाल के दिनों में, राजभवनों ने विपक्ष शासित राज्यों में राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों में देरी करके एक अवरोधक भूमिका निभाई है।

चूंकि अदालत ने राष्ट्रपति को विलंब के परिणामों पर सख्त समय-सीमा का निर्देश दिया था, इसलिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सवाल उठा। मई में सर्वोच्च न्यायालय को भेजे एक संदर्भ में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस फैसले पर 14 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या न्यायालय ने राज्यपालों द्वारा उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के प्रयास में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अतिक्रमण किया है, जो संविधान के मूल ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अदालत ने अब संतुलित रुख अपनाते हुए अपनी सलाह में कहा है कि न्यायपालिका को 'विधायी प्रक्रिया में दखलंदाज़ी' की अनुमति देना 'शक्तियों के पृथक्करण की दीवारों को तोड़ना' होगा।' साथ ही यह भी कहा, 'इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायिक समीक्षा भी मूल ढांचे का एक हिस्सा है... हालांकि, यह न्यायिक समीक्षा कोई बेलगाम दायरा नहीं है जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को नकार या नष्ट कर सके।' केंद्र सरकार ने भी अप्रैल के फैसले को लेकर टकराव पैदा करने के बजाय, न्यायालय से राय मांगकर अच्छा किया। वस्तुतः राज्यपाल को 'रबर स्टैंप' मानना भी अनुचित है। संविधान ने राज्यपाल को एक ऐसी कड़ी के रूप में देखा है जो बहुस्तरीय व्यवस्था के दो स्तरों को जोड़ती है, न कि उन्हें विभाजित करती है। अलबत्ता अब न्यायालय की राय यह भी दर्शाती है कि उसकी भूमिका 'स्पष्ट परिस्थितियों' तक सीमित है।

अब अदालत ने अपनी सलाह में कहा है कि राज्यपालों की तथाकथित 'निष्क्रियता' के बावजूद, 'संवैधानिक न्यायालय राज्यपाल और राष्ट्रपति के विवेक और विचारों का स्थान नहीं ले सकते।' तमिलनाडु विधानसभा से पास होने के बावजूद दस विधेयकों को रोक कर रखने के राज्यपाल आरएन रवि के फैसले को अवैध करार देते हुए अप्रैल में उच्चतम न्यायालय ने एक संवैधानिक पेच को खोल ज़रूर कर दिया, पर इससे केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यपालों की भूमिका से जुड़ी पहेलियों का हल पूरी तरह नहीं हुआ था।

हाल के वर्षों में कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य विधान परिषदों में नामांकन और राज्यपाल द्वारा पारंपरिक अभिभाषण के संपादन या सदन को बुलाने पर दुर्भाग्यपूर्ण रस्साकशी तो हुई ही है, विधानमंडलों से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी या इनकार जैसे कार्य भी हुए हैं। तमिलनाडु, केरल और बंगाल में सरकारों और राज्यपालों के बीच ऐसे कई विवाद खड़े हुए हैं।

विधानमंडल से पास हुए विधेयकों को रोकने की शक्ति को लेकर 2023 में, पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राज्यपाल निर्वाचित विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अदालत के अप्रैल के फैसले ने उस समयबद्धता को परिभाषित भी कर दिया। इससे विधानमंडल से पास हुए विधेयकों के बारे में राज्यपालों का विशेषाधिकार सीमित हो गया था। इस निर्णय का महत्व तमिलनाडु के राज्यपाल की निंदा से कहीं अधिक था।

अप्रैल में न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को 'शीघ्रता से काम करना चाहिए' और किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोककर वे 'पॉकेट वीटो' का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनुच्छेद 200 को अनुच्छेद 163 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य करता है। यदि कैबिनेट की सलाह के विपरीत राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी नहीं देते हैं या उसे सुरक्षित रखते हैं, तो उन्हें ऐसा तीन महीने के भीतर करना होगा। दोबारा पारित विधेयकों के लिए समय-सीमा घटाकर एक महीना कर दी गई।

तमिलनाडु सरकार ने शनिवार, 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से छूट देने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी न दिए जाने के फैसले को फिर चुनौती दी है। 'नीट' से छूट हासिल करना राज्य के दशकों पुराने नीतिगत विमर्श का फिलहाल अनिर्णीत अध्याय है।

केंद्रीय नीति के खिलाफ राज्य का कानून बनाने का इतना लंबा कोई अन्य प्रयास नहीं रहा है। सितंबर 2017 में, 'नीट' विरोधी दो विधेयकों का राष्ट्रपति भवन में यही हश्र हुआ। चार साल बाद, सत्तारूढ़ डीएमके ने, 'नीट' से छूट को अपना चुनावी वायदा बनाया। सरकार बनाने के बाद जस्टिस एके रंजन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विधानसभा में 2021 में विधेयक पारित किया। उसे स्वीकृति नहीं मिली, जिसे लेकर सरकार अब फिर सुप्रीम कोर्ट गई है।

प्रेरणा

एक प्रार्थना, जो किसी मंदिर में नहीं-मन के सबसे शांत कोने में जन्म लेती है

मार्गशीर्ष की ठंडी हवा उस सुबह कुछ अलग ही थी। पूरा गाँव हल्के कुहासे से ढका हुआ था और आसमान में कहीं एक हल्की सुनहरी रेखा तैर रही थी, मानो सूर्य खुद भी आज थोड़ा देर से जागना चाहता हो। यह वही दिन था जब विनायक चतुर्थी पड़ती थी—वह तिथि, जब लोग भगवान गणेश से अपने जीवन के सारे अटके हुए कामों को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। पर इस बार गाँव के माहौल में कुछ बदला हुआ था, जैसे हवा में कोई पुरानी कथा फिर से जाग उठी हो, कोई भूला हुआ आशीर्वाद फिर से लौट आया हो।

गाँव के बीचोंबीच एक छोटा-सा पुराना मंदिर था—उसके पत्थरों में बीते युगों की थकान भी थी और आस्था की ताजगी भी। लोग सुबह-सुबह वहीं इकट्ठा होते, पर एक आदमी ऐसा था जिसकी पदचाप सबसे पहले उस मंदिर की देहरी छूती थी। उसका नाम कोई ठीक से नहीं जानता था—लोग उसे बस "गणेश दास" कहते थे। वह सचमुच गणेश का दास न था, पर गाँव में यह मान्यता थी कि उसके भीतर कोई ऐसी ज्योति है जो सामान्य लोगों में नहीं होती।

कहते हैं कि बरसों पहले वह किसी बड़े नगर में पढ़ता था। उसका परिवार सम्पन्न था, और उसका जीवन भी बिल्कुल अलग रहा करता था। लेकिन एक दिन, अचानक, वह सब छोड़कर इस गाँव में चला आया। लोग पूछते, तो वह बस मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने आत्मा के सबसे छिपे हुए कोने में दीपक जला दिया हो—बिना किसी दुःख की छाया, बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए, सहसा प्रकाशित और बिल्कुल सहज।

वह मंदिर में पहले पहुँचता, घंटा बजाता, और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता। उसके स्वर में कोई कठोरता नहीं थी—मानो वह मंत्र केवल पढ़ नहीं रहा, बल्कि अपनी साँसों में उन्हें पिरो रहा हो, जैसे संसार का हर कण उसके स्वर में तैरता हुआ शांत हो जाता हो। लोग कहते कि जो काम वर्षों से अटका हो, वह उसके जपे हुए मंत्रों के बाद अचानक सरल हो जाता है।

गाँव के पंडित को भी उसकी उपस्थिति अजीब लगती थी—वह एक अद्भुत तेज लिए घूमता, और कोई भी उससे नाराज़ नहीं रह पाता। बच्चे उसे प्यार करते, बूढ़े उसका सम्मान करते, और महिलाएँ उससे दूर ही रहतीं—शायद इसलिए क्योंकि उसकी आँखों में कोई ऐसा संयम था, कोई ऐसा सौम्य त्याग, जो स्त्रियाँ सहज ही समझ जाती हैं।

उस दिन—विनायक चतुर्थी की विशेष सुबह—वह पहले से भी ज्यादा शांत था। उसने मंदिर की चौखट पर पैर रखते ही आँखें बंद कर लीं, जैसे किसी अनदेखी हवा ने उसका चेहरा छू लिया हो। कुहासे के बीच से सूरज की एक पतली किरण सीढ़ियों पर गिर रही थी। उसने धीरे से दीप जलाया, फूल चढ़ाए, और फिर मंत्र जप शुरू किया। उसका स्वर इतना धीरे, इतना गहरा था कि वह स्वर नहीं, किसी पुरानी स्मृति की प्रतिध्वनि लगते थे।

लेकिन कोई जानता नहीं था कि उसकी हंसी क्यों गुम हो गई थी और उसकी आँखों में वह अनकहा दर्द कहाँ से आता था। गाँव में एक ही अफवाह थी कि कभी उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह बेहद चाहता था। किसी ने कहा—वह पत्नी थी, किसी ने कहा—मंगेतर, किसी ने कहा—उसकी प्रेमिका। पर सच किसी को नहीं पता था। हाँ, इतना जरूर पता था कि जब से वह व्यक्ति उससे अलग हुआ, वह आदमी हंसना भूल गया था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं आती थी—सिर्फ एक शांत, स्थिर, गंभीर प्रकाश था, जो दूसरों के लिए शांति का कारण बनता था, पर उसके भीतर कहीं एक अधूरा गीत चुपचाप दबा हुआ था।

उसने उस सुबह जो मंत्र बोले—वे गाँव की हवा में एक थरथराहट पैदा कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि उसकी आवाज अलग लग रही थी, जैसे वह स्वयं गणेश से कुछ मांग रहा हो। पहली बार उसने अपने लिए प्रार्थना की थी। पहली बार उसने अपने टूटे हुए दिल का एक टुकड़ा मंत्रों में रखकर देवता के चरणों में रख दिया था। वह धीमी आवाज में कह रहा था, "हे विघ्नहर्ता, मेरे भीतर जो अवरोध हैं, उन्हें दूर कर दो। मुझे मेरी अधूरी कहानी से मुक्त कर दो।"

मंदिर में बैठे बूढ़े ने पहली बार देखा कि उसकी आँखें नम थीं। बूढ़े ने उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा कि कितनी अजीब बात है—जो आदमी दूसरों के सारे विघ्न दूर करता है, उसके अपने ही विघ्न कोई नहीं देख पाता।

उस शाम लोग कह रहे थे कि उनके काम बनने लगे थे—किसी का बकाया पैसा मिल गया, किसी की रुकी नौकरी लग गई, किसी की बहू का इलाज सफल रहा। गाँव में लोग उसी को इस चमत्कार का कारण मानते रहे। पर वह आदमी चुप-सा चला जाता, जैसे उसके लिए चमत्कारों का कोई अर्थ नहीं रहा हो। वह तो बस उस आवाज़ का इंतज़ार कर रहा था—एक ऐसी आवाज़, जिसने वर्षों पहले उसकी दुनिया बदली थी और फिर उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गई थी। रात हुई तो वह मंदिर में फिर लौटा। अकेले। बिना किसी आडंबर के। उसने दीप जलाया, और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आँखें बार-बार गीली हो उठीं, पर होंठों पर कोई शिकायत नहीं आई। वह जानता था—कुछ दर्द समय से नहीं मिटते, केवल आत्मा की सतह से नीचे उतरकर शांत हो जाते हैं। उसने आखिरी बार मंत्र पढ़ा, फिर अपनी हंसी की जगह एक धीमी-सी साँस छोड़ी—जैसे कोई पुराना बोझ हवा में घुलकर हल्का हो गया हो।

और कहा जाता है कि उस विनायक चतुर्थी की रात उसके भीतर कुछ बदल गया—न कोई चमत्कार, न कोई दिव्यता, बस एक गहरी, शांत स्वीकृति। जैसे उसने जीवन को ऐसे स्वीकार कर लिया हो, जैसे वह वर्षों से इसे स्वीकार करना चाह रहा था।

गाँव वाले अगले दिन भी उसे मंदिर में देखने को आए—वह वहीं था। वही शांत चेहरा, वही सौम्य आँखें, पर एक नई-सी चमक थी। एक हल्की मुस्कान लौट आई थी—वही नहीं, लेकिन कुछ उसके जैसी—जैसे कोई टूटा हुआ दीपक फिर से जल उठा हो, थोड़ा कम उजाला करता हुआ, पर उतना ही सच्चा। और लोग कहते हैं—उस दिन से उसका जपा हुआ मंत्र और भी प्रभावी हो गया। क्योंकि पहली बार वह मंत्र सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी सच हो गया था।

झूठे आरोपों पर टिका विपक्ष, भाजपा की राजनीतिक बढ़त रोकने के लिए गढ़ रहे नैरेटिव

नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दसवीं बार शपथ ले ली और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया, पर यह चर्चा थम नहीं रही कि आखिर राजग ने इतनी प्रचंड जीत कैसे हासिल कर ली। चुनावी जीत कई कारणों पर निर्भर करती है। बिहार में राजग की जीत के भी कई कारण रहे।

एक बड़ा कारण रहा जदयू-भाजपा के साथ उसके अन्य सहयोगी दलों के बीच बेहतर सीट बंटवारा और तालमेल। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख कारण है नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार का पटरी पर आना। इसका संज्ञान इसलिए अधिक लिया गया, क्योंकि इसके पहले लालू-राबड़ी यादव का शासनकाल इस कदर जंगलराज का पर्याय बन गया था कि पिछले चुनावों की तरह इस चुनाव में भी मुद्दा बना और उसने अपना असर भी दिखाया।

विपक्ष यह सब देखने से इन्कार कर रहा है। विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस वोट चोरी का ही राग अलाप रही है। वोट चोरी का आरोप चुनावों के पहले तभी उछाल दिया गया था, जब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराना शुरू ही किया था। विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाकर धरना-प्रदर्शन करने के साथ वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली, लेकिन चुनाव आते-आते यह कोई मुद्दा ही नहीं रहा।

चुनाव बाद के आंकड़े यह बताते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे, वहां कहीं राजग जीता तो कहीं विपक्ष। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि राजग को एसआईआर का लाभ मिला। मतदाता सूची से लाखों नाम कट जाने के बाद भी किसी ने यह शिकायत नहीं की कि उसका नाम गलत तरीके से काट दिया गया है। यानी जो नाम कटे, वे सही कटे। यदि ऐसा नहीं होता लोगों ने सड़कों पर उतरकर शिकायत की होती। ऐसे लोगों को सामने लाकर राजनीतिक दल भी शिकायत नहीं कर सके तो इसीलिए कि उन्हें कोई ऐसा मिला ही नहीं।

चुनाव आयोग ने बिहार में कम समय में जिस तरह एसआईआर कराया और उसके उपरांत सफलतापूर्वक चुनाव कराए, इसके लिए उसे साधुवाद दिया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष उसकी आलोचना करने के साथ नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित क्षेत्रों में हो रहे एसआईआर का विरोध कर रहा है। विपक्ष शासित राज्य और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल एसआईआर का कुछ ज्यादा ही विरोध कर रहे हैं।

बंगाल की मुख्यमंत्री ने एसआईआर के विरोध में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और उसे अनावश्यक बताया है। वे ऐसा इसके बाद भी कह रही हैं कि बंगाल में रह रहे हजारों बांग्लादेशी वापस अपने देश लौट रहे हैं। यह एसआईआर का ही असर है कि तमाम बांग्लादेशी बांग्लादेश लौटने को आतुर हैं। वे इसीलिए लौट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घुसपैठ की थी। उनके बांग्लादेश लौटने से गृहमंत्री अमित शाह की यह बात सही सिद्ध होती है कि देश में घुसपैठिए रह रहे हैं और वे भारत के ससांधनों का दोहन कर रहे हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में अवैध रूप से आ बसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। उन्हें निकालने के लिए अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए, क्योंकि यह काम चुनाव आयोग का नहीं कि वह घुसपैठियों के खिलाफ कदम उठाए। बांग्लादेशी घुसपैठिए इसीलिए लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एसआईआर के चलते उनकी पोल खुल जाएगी।

यह उम्मीद की जाए कि एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया से बंगाल समेत सभी राज्यों में वोटर लिस्ट दुरुस्त होगी। चूंकि इसके पहले वोटर लिस्ट ठीक करने का काम करीब दो दशक पहले हुआ था, इसलिए उसमें तमाम खामियां घर कर गई हैं। वोटर लिस्ट में केवल दोहराव ही नहीं है, उनमें मृतकों और अन्यत्र बस गए लोगों के नाम भी दर्ज हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट का सही होना आवश्यक है।

समझना कठिन है कि विपक्षी दलों को वोटर लिस्ट ठीक किए जाने से क्या परेशानी है। वे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत भी करते हैं और एसआईआर भी नहीं होने देना चाहते। आखिर एसआईआर पहली बार तो हो नहीं रहा। उसे कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर पर रोक लगाने की जरूरत नहीं समझी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईआर को जरूरी बताए जाने के बाद भी विपक्षी दल यह माहौल बना रहे हैं कि इसके जरिये भाजपा चुनाव जीतने के लिए जोड़तोड़ करती है और चुनाव आयोग उसका साथ देता है।

इसी शिकायत के साथ 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। बिहार में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस तरह एक रैली करने जा रही है, उससे साफ है कि वह इस मुद्दे पर अपने झूठे अभियान को जारी रखेगी। इसके संकेत राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं के चुनाव आयोग के खिलाफ आए बयानों से मिल रहा है।

राहुल गांधी चुनाव आयोग को जिस तरह निशाने पर ले रहे हैं, वह एक संवैधानिक संस्था का अपमान ही है। वे संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश में खुद के साथ अपने दल को ही कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को सही मान रहा है। भले ही विपक्षी नेताओं समेत कुछ कथित लोकतंत्र हितैषी 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हों, पर इसमें संदेह है कि वे वहां से इस प्रक्रिया को रुकवा सकेंगे।

विपक्ष यह समझने से इन्कार कर रहा है कि वह झूठे आरोपों के सहारे न तो जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ा सकता है और न ही भाजपा की राजनीतिक बढ़त को रोक सकता है। बिहार में बड़ी जीत के साथ देश भर में भाजपा के विधायकों की संख्या 1654 हो चुकी है, जो उसके लिए एक रिकार्ड है। आने वाले समय में उसके विधायकों की संख्या में और वृद्धि होना तय है।

यदि विपक्ष को भाजपा की राजनीतिक बढ़त रोकनी है तो उसे अपना नैरेटिव ऐसा बनाना होगा, जिससे वह लोगों का भरोसा जीत सके। यह काम झूठे आरोपों के सहारे नहीं हो सकता।

अभियान

जब चतुर्थी की भोर में बज उठी पहली घंटी और गणेश मंत्रों की दिव्य ध्वनि ने पूरे गाँव को आशीर्वाद की सुनहरी रोशनी में डुबो दिया

मार्गशीर्ष का महीना हमेशा से ही अपने भीतर एक अद्भुत शांति समेटे रहता है, लेकिन उस वर्ष की विनायक चतुर्थी कुछ अलग ही प्रतीत हो रही थी। रात ढलते ही गाँव के ऊपर आकाश में सितारे पहले से ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धरती पर उतरने वाली हो। सरकंडे की झाड़ियों में से आती धीमी हवा मिट्टी की महक को अपने साथ लिये गलियों में घूम रही थी। ऐसा लगता था कि प्रकृति स्वयं किसी दिव्य अतिथि के आगमन के स्वागत में व्यस्त है। और वही था — भगवान गणेश का पावन दिन, वह चतुर्थी जिसे भक्त पूरे मन, पूरे विश्वास, पूरे प्रेम से मनाते हैं। गाँव के मंदिर में उस दिन एक अलग ही हलचल थी। पुजारी जी भोर से पहले उठकर मंदिर की सीढ़ियाँ धो रहे थे, और उन सीढ़ियों पर गिरती हर बूंद सूर्योदय से पहले ही चमकने लगती थी मानो अंधकार भी उस पवित्र स्पर्श के आगे झुक रहा हो। कुछ महिलाएँ घरों में मोदक और लड्डू बना रही थीं, जिनकी मीठी गंध पूरे वातावरण में फैल कर एक अनजानी खुशी जगाती जा रही थी। छोटे-छोटे बच्चे अपने मन में तमाम इच्छाएँ सजा कर गणपति के सामने रखने की तैयारी में थे—किसी को परीक्षाओं में सफलता चाहिए थी, किसी को नया खिलौना, किसी को अपने पिता का गुस्सा कम चाहिए था और किसी को सिर्फ इतना कि भगवान गणेश उनकी माँ को हमेशा खुश रखें। जब पहली किरण क्षितिज से निकली, तब ऐसा लगा मानो पूरा आकाश एक क्षण के लिए रुक कर देख रहा है कि आज पृथ्वी पर गणेश भक्त क्या ले कर आए हैं। और उस समय गाँव का हर व्यक्ति अपने-अपने घरों में स्नान कर, नए-स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा की थाली सजाने में लगा था। कोई चंदन घिस रहा था, कोई दूर्वा की पत्तियाँ गिन रहा था, कोई लाल फूल चुन रहा था और कोई दीपक का तेल भर रहा था। सबके चेहरों पर भक्ति का तेज किसी साधक की तरह झलक रहा था। मंदिर में प्रवेश करते ही लोगों के मन में एक अद्भुत शांति उतर जाती थी। भगवान गणेश की मूर्ति उस दिन कुछ अलग ही दिख रही थी। हाथों में मोदक, सूँड़ पर हल्की मुस्कान और आँखों में वह गहराई जो सीधे आत्मा को छू जाए—ऐसा लगता था जैसे गणपति स्वयं कह रहे हों—"जो भी चिंता है, मेरे चरणों में रख दो मैं संभाल लूँगा।" और लोग भी सचमुच उसी भाव से अपने मन की हर उलझन, हर

घबराहट, हर पीड़ा उनके सामने रख देते थे।

आरती शुरू होते ही मंदिर की घंटियाँ ऐसी बज उठीं कि पूरा गाँव उस ध्वनि से गूँज उठा। वही क्षण वह था जब पुजारी जी ने वह मंत्र बोलना शुरू किया जिसे सुनने भर से मन का सारा बोझ उतर जाता है—

ॐ गं गणपतये नमः

और लोगों की आवाजें भी उसी लय में जुड़ गईं। हर एक शब्द, हर एक ध्वनि, हर एक कंपन हवा में दूर तक फैलता गया। ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड की हर दिशा उस मंत्र का प्रत्युत्तर दे रही हो। वातावरण में उठता वह कंपन किसी साधना, किसी तपस्या, किसी दिव्य ऊर्जा का रूप लग रहा था।

गाँव की एक बुजुर्ग महिला, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे वर्षों से गणपति के उपासक थे, धीरे से बोलीं कि आज यदि कोई अपने मन की इच्छा बोल दे, और गणेश मंत्र का जप करे, तो उसका काम अवश्य पूर्ण होगा, चाहे वह कितना भी अटका हुआ हो। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि जब सारी आशाएँ टूट गईं, तब केवल एक मंत्र— वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ

ने पलभर में ऐसे परिणाम दिए जिन्हें चमत्कार कहने में भी कोई संकोच नहीं था। दिन धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और सूरज आसमान में ऊँचा चढ़ गया, परंतु भक्ति का उत्साह कम नहीं हुआ। लोग मंत्रों का जप करते रहे—कभी धीमे स्वर में, कभी पूरे जोश के साथ, कभी आँखें बंद करके, कभी आँसू बहाते हुए। हर किसी को विश्वास था कि गणेश जी उनके जीवन की वह राह दिखा देंगे जो अभी तक धुंध में छिपी हुई थी।

संध्या का समय आया तो हवा और भी ठंडी हो गई। दीपक की लौ हल्की-हल्की डोलने लगी जैसे किसी प्राचीन कथा का संगीत हवा में घुल रहा हो। उस समय जब अंतिम मंत्रोच्चार किया गया, तब ऐसा लगा मानो समय थम गया है। बच्चों की हँसी मंद हो गई, हवा भी स्थिर सी हो गई, और हर व्यक्ति के हृदय में एक दिव्य शांति उतर आई।

लोगों ने न सिर्फ प्रसाद ग्रहण किया, बल्कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके भीतर कोई नया आत्मविश्वास जाग उठा हो। किसी को लगा कि उसकी अटकी हुई नौकरी अब निश्चित रूप से मिलेगी, किसी को लगा कि उसके घर का कलह अब समाप्त होगा, किसी को विश्वास हुआ कि उसका व्यापार अब नई राह पकड़ेगा। किसी को यह अहसास हुआ कि वे अब अकेले नहीं हैं—क्योंकि गणेश जी उनके साथ चलने वाले हैं।

इस प्रकार वह चतुर्थी न सिर्फ एक पर्व रही, न सिर्फ पूजा रही, बल्कि एक जीवित कथा बन गई—एक ऐसी कथा जो हर वर्ष नए अनुभव, नई भावनाएँ, नई आशाएँ लेकर लौटती है। और जो भी भक्त उस रात भगवान गणेश के मंत्रों का जप करता है, वह यह समझ लेता है कि विघ्नहर्ता केवल एक देवता नहीं, बल्कि वह ऊर्जा हैं जो जीवन के हर ताले की चाबी बन सकती है, यदि मन सच्चे भाव से उन्हें पुकारे।

यदि आपके जीवन में भी किसी कार्य में रुकावट है, अगर कोई मार्ग धुंधला लग रहा है, अगर मन में भय या संदेह की परछाई है, तो इस पावन विनायक चतुर्थी पर मंत्र जप अवश्य करें। क्योंकि जब गणेश जी की कृपा उतरती है, तब न केवल बाधाएँ हटती हैं, बल्कि जीवन स्वयं प्रकाश बनकर खिल उठता है, और हर मनोकामना अपनी पूरी चमक के साथ सत्य होने लगती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नवगठित गांधीधाम महानगर पालिका को एक ही दिन में एक साथ 176 करोड़ रुपए के 66 विकास कार्यों की भेंट दी

▸▸ नगर पालिका से महानगर पालिका बने गांधीधाम शहर में आकार लेने वाले मॉडल फायर स्टेशन, स्मार्ट लाइब्रेरी, आइकॉनिक प्रवेश द्वार, उद्यान, सड़कों, सीवरेज, जल और स्टॉर्म वाटर जैसे विकास कार्यों से शहर को मिलेगी एक नई पहचान

▸▸ गोपालपुरी गेट से सर्वोदय क्रिकेट ग्राउंड तक की सड़क गौरव पथ के रूप में विकसित की जाएगी

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▸▸ गुजरात के अहम औद्योगिक केंद्र और कच्छ की आर्थिक राजधानी गांधीधाम को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरीकरण को चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करके सुनियोजित शहरी विकास की दिशा दिखाई

▸▸ गुजरात में समग्र शहरी विकास के लिए शहरी विकास बजट में 40 फीसदी की वृद्धि के साथ राज्य सरकार ने किया 30 हजार करोड़ रुपए का आवंटन

▸▸ गांधीधाम मनपा के 176 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोगों की सुविधा और खुशहाली के लिए दी गई 'ईज ऑफ लिविंग' की संकल्पना और सर्वग्राही विकास को सार्थक करेंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : नगर पालिका से महानगर पालिका बनने के बाद रविवार को पहली बार गांधीधाम शहर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शहर को 176 करोड़ रुपए के 66 विकास कार्यों की सौगात दी।

इसके साथ ही, उन्होंने ओस्लो सर्कल में डॉ. बाबासाहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी पुनर्स्थापित प्रतिमा का अनावरण और नवनिर्मित फ्लाईओवर का 'डॉ. बाबासाहब अंबेडकर' नामकरण किया तथा सर्कल डेवलपमेंट और पार्किंग सुविधा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

गांधीधाम के गोपालपुरी स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 176 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ई-शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने महानगर के नागरिक के रूप में गौरव प्राप्त करने के लिए गांधीधाम वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गांधीधाम महानगर पालिका के गठन के बाद उनका पहली बार यहां आना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और राज्य सरकार कच्छ की आर्थिक राजधानी के रूप में जाने जाने वाले और राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र गांधीधाम को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प हैं। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 176 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकास का रोल मॉडल बन चुके गुजरात में बढ़ते विकास के कारण लोग रोजी-रोटी के लिए नगरों में बस रहे हैं। ऐसे में, नगरों में जन कल्याण और बुनियादी सुविधाओं के कार्यों में गति लाने के लिए राज्य सरकार नई महानगर पालिकाओं का गठन कर रही है।

इसी विजन के अंतर्गत विकास की गति और व्यापकता को बढ़ाने के लिए गांधीधाम नगर पालिका में आसपास के 11 गांवों को शामिल कर नई महानगर पालिका का गठन किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि पहले गांधीधाम नगर पालिका का सालाना बजट 110 करोड़ रुपए था, लेकिन महानगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद इससे छह गुना अधिक यानी 608 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।

इतना ही नहीं, गांधीधाम को शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं से पिछले तीन वर्षों में 255 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने गांधीधाम महानगर पालिका द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समग्र शहर के विकास की सोच को साकार करने वाले ये कार्य सर्वग्राही विकास की झलक दिखाते हैं। समय के अनुकूल और नगर की प्राथमिक आवश्यकताओं के कार्यों में आइकॉनिक रोड, सड़कें, पानी, सीवरेज, उद्यान-तालाब सहित जन-जन को छूने वाले विकास कार्यों के साथ ही मनपा ने फायर स्टेशन और मॉडर्न लाइब्रेरी जैसे आधुनिक विकास कार्यों को भी शामिल किया है, जो सर्वग्राही विकास को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के शहरों ने देश को बताया है कि शहरों का विकास कैसा होना चाहिए, किस स्केल का और किस स्पीड का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले केवल विकास की बातें ही होती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास की राजनीति के जरिए विकास को धरातल पर उतारा है। प्रधानमंत्री ने कच्छ को भूकंप की आपदा से उबारकर विकास की राह पर तेज गति से अग्रसर किया है। प्रधानमंत्री के विजन और विकास से व्यापार, उद्योग, रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में गुजरात ने विकास की चरम सीमा को पार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरीकरण को चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करके सुनियोजित शहरी विकास की दिशा देश को दिखाई है। प्रधानमंत्री ने शहरी विकास के विजन को साकार करने के लिए योजनाबद्ध और समयानुकूल शहरी विकास के लिए 2005 में शहरी विकास वर्ष मनाने के बाद गुजरात की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2010 में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना लागू की थी। छोटे शहरों के लिए बड़ी सुविधाएं प्रदान करने वाली इस योजना के तहत राज्य सरकार ने पिछले डेढ़ दशक में 57 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि का प्रावधान किया है।

प्रधानमंत्री ने नगर पालिका और महानगर पालिकाओं में क्षमता निर्माण एवं सशक्तिकरण के समयबद्ध आयोजन के माध्यम से समग्र शहरी विकास के सफल प्रयोग दिए हैं। राज्य सरकार उनकी इस सोच के अनुरूप शहरों के सुनियोजित विकास के साथ 'अर्निंग वेल, लिविंग वेल' यानी बेहतर कमाई और बेहतर जीवन के मंत्र को चरितार्थ करने के लिए 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मना रही है।

इसके लिए शहरी विकास के बजट में गत वर्ष की तुलना में 40 फीसदी की वृद्धि कर 30 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शहरी विकास को एक बेंचमार्क तक पहुंचाए जाने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमें भविष्य की जरूरतों के मुताबिक शहरों का विकास करना है। इसके लिए शहरों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के प्रत्येक क्षेत्र की क्षमताओं को पहचान कर उसके विकास की मजबूत नींव रखी है और वाइब्रेंट समिट के जरिए गुजरात के औद्योगिक विकास को दुनिया में एक नई दिशा और ऊंचाई प्रदान की है। उनके इस विजन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने, स्थानीय उत्पादन बढ़ाने और रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य सरकार रीजनल वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। इससे निवेश अधिक से अधिक बढ़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनवरी में राजकोट में आयोजित होने वाली सौराष्ट्र–कच्छ की वाइब्रेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस कच्छ स्थित बड़े उद्योगों के अनुरूप स्थानीय उद्योगों के विकास और अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आज ही से शहरों को भविष्योन्मुखी बनाने के आयोजन पर जोर देते हुए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' सूत्र के जरिए टिकाऊ शहरों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने और गांधीधाम से इस पहल का नेतृत्व करने का अनुरोध किया।

उल्लेखनीय है कि नगर पालिका से महानगर पालिका बनने के बाद पहली बार गांधीधाम शहर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का लोगों ने एयरपोर्ट से लेकर गोपालपुरी तक विभिन्न क्षेत्रों में ढोल-नगाड़ों के साथ भावपूर्ण स्वागत किया।

मुख्यमंत्री के स्वागत में गांधीधाम शहर के विभिन्न समाज के नागरिक शामिल हुए और राज्य सरकार के सर्व समावेशी विकास की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। इस मौके पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा ने कहा कि विभाजन की वेदना से खड़ा हुआ यह गांधीधाम शहर आज आर्थिक और बंदरगाह गतिविधियों में भारत का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विकसित गांधीधाम के विकास को और तेज गति देने के लिए राज्य सरकार ने इसे महानगर पालिका का दर्जा दिया है, जिससे इस शहर का योजनाबद्ध तरीके से और विकास संभव हो पाएगा।

राज्य मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का कच्छ के प्रति विशेष प्रेम है और इसी प्रेम के कारण ही उन्होंने कच्छ का सार्वत्रिक विकास किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल इसी विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। कच्छ के प्रति विशेष आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री ने नर्मदा जल और सड़कों सहित विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान कर कच्छ की विशेष रूप से चिंता की है।

कार्यक्रम में सांसद श्री विनोदभाई चावड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जनकसिंह जाडेजा, विधायक श्रीमती मालतीबेन महेश्वरी, विधायक श्री विरेन्द्रसिंह जाडेजा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती नीमाबेन आचार्य, मनपा आयुक्त श्री मनीष गुरुवाणी, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन श्री सुशील कुमार सिंह, अग्रणी श्री देवजीभाई वरचंद, श्री धवलभाई आचार्य, पूर्व नपा अध्यक्ष श्री तेजस शेठ सहित कई अग्रणी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

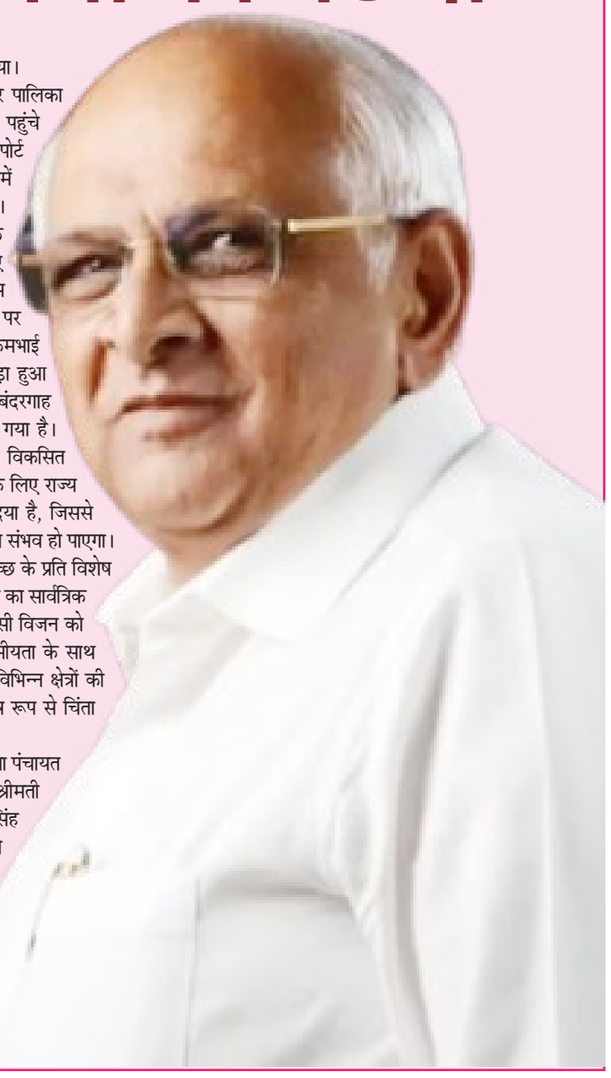

'शंटिंग मेला' का सफल आयोजन

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल के परिचालन विभाग द्वारा सुरक्षित ट्रेन परिचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में गोधरा स्टेशन पर "शंटिंग मेला" का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संरक्षा पश्चिम रेलवे के लिए सर्वोपरि है। इसी क्रम में परिचालन विभाग के कर्मचारियों के लिए गोधरा में शंटिंग मेला आयोजित किया गया, जिसमें 107 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में प्रश्नोत्तर सत्र एवं खुली चर्चा के माध्यम से प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस मेले के अंतर्गत आयोजित सेमिनार में परिचालन विभाग के रेल कर्मचारियों से शंटिंग कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियाँ, लोड की स्टेबलिंग के समय आवश्यक एहतियात, पावर ब्लॉक के दौरान सुरक्षा उपाय, दिन एवं रात में हाथ संकेतों का उपयोग, पॉइंट्स की क्लैम्पिंग के समय सावधानियाँ आदि के बारे में उच्च अधिकारियों द्वारा खुली चर्चा की गई और उनको संरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूक किया गया।

श्री सक्सेना ने बताया कि वडोदरा मंडल के परिचालन विभाग की यह पहल रेलवे कर्मचारियों में सुरक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करने, स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने तथा निरंतर सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है।

अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2025 : 11 दिनों में 8 .21 लाख से अधिक पुस्तक प्रेमियोंने भाग लिया

(जीएनएस)। अहमदाबाद : साबरमती रिवरफ्रंट इवेंट सेंटर में 13 से 23 नवंबर तक आयोजित अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2025ने इस बार लोकप्रियता का नया इतिहास रचा है। इस 11 दिवसीय महोत्सव में कुल 8.21 लाख से अधिक आगंतुकोंने भाग लिया, जिससे यह साहित्यिक उत्सव न केवल राज्य में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे अधिक दर्शकों वाला पुस्तक महोत्सव बन गया है।

13 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथों इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। वंदे मातरम के समूहगान और स्वदेशी प्रोत्साहन प्रतिज्ञा से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित पुस्तक 'बैरिस्टर मिस्टर पटेल' सहित कई पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया।

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लगभग 1 लाख वर्गफुट के विशाल परिसर में बनाए गए इस महोत्सव में 300 से अधिक प्रकाशकों ने भाग लिया। शहर के सभी आयु वर्गों के लिए तीन विशेष ज़ोन बनाए गए थे, जिनमें बाल साहित्य, रचनात्मक सत्र, काव्य पाठ, लेखकों के साथ संवाद, वर्कशॉप्स और फ़िल्म फेस्टिवल जैसी गतिविधियाँ लगातार दर्शकों को आकर्षित करती रहीं।

इस बुक फेस्टिवल में बच्चों की कार्यशालाएँ, कहानी वाचन, कला–हस्तकला कार्यक्रम और चिल्ड्रन फ़िल्म फेस्टिवल ने विशेष लोकप्रियता हासिल की। स्कूल बोर्ड के शताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हज़ारों विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया।

युवाओं के लिए आयोजित 'ज्ञान गंगा' वर्कशॉप्स ने भी महोत्सव की ज़बरदस्त सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कविता लेखन, नाटक, फ़िल्म स्क्रिप्टिंग और बुक डिज़ाइन जैसी रचनात्मक कार्यशालाओं के साथ-साथ विभिन्न पुस्तक लोकार्पण सत्रों ने विद्यार्थियों, लेखकों और रचनाकारों को एक साथ जोड़ा।

इसके अलावा विदेशी वक्ताओं की उपस्थिति ने इस महोत्सव को वैश्विक पहचान दी। चिली, स्पेन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से आए चर्चित विचारकों ने भारतीय साहित्य और संस्कृति से जुड़े विषयों पर विशेष सत्र प्रस्तुत किए। साथ ही मुख्य मंच पर प्रतिदिन आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने महोत्सव को जीवंत बनाए रखा। इस महोत्सव को इसकी उत्कृष्ट व्यवस्था और सुविधाओं के कारण भी खूब सराहा गया। स्वच्छ परिसर, विशाल फूड कोर्ट, स्टार्टअप ज़ोन, वीआर गेमिंग का अनोखा स्टैम्प प्रदर्शन और पाठन के लिए अनुकूल वातावरण ने कई परिवारों को यहाँ लंबे समय तक समय बिताने के लिए आकर्षित किया। इस प्रकार आयोजकों की मेहनत और उत्कृष्ट प्रबंधन के चलते अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2025 को 'ज्ञान का महाकुंभ' के रूप में विशेष पहचान मिली है।

...यह बात ध्यान में आते ही मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाकर तुरंत ही कार्यक्रम का स्थल बदला !

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का मानवतावादी दृष्टिकोण

▸▸ एक बेटी का विवाह पूर्व निर्धारित समय तथा स्थल पर आयोजित हो; इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर के कार्यक्रम का स्थल बदला

▸▸ "हमारे कार्यक्रम का स्थल बदलो, बेटी के परिवार की चिंता हमारी चिंता" : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ "विवाह के मौसम में तत्काल नया स्थल खोजना, मेहमानों को सूचित करना, नई व्यवस्थाएँ करना; ये सब हमारे लिए मुश्किल था, परंतु मुख्यमंत्री साहब का एक फोन आया और उस रात हम शांति से सो सके" : श्री ब्रिजेश परमार, बेटी के काका

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाने वाली घटना प्रकाश में आई है। हुआ हूँ कि मुख्यमंत्री ने जामनगर के एक परिवार की विनती को सम्मान देकर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का स्थल बदल दिया, जिससे एक बेटी के विवाह का प्रसंग धूमधाम से और शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। बात विस्तार से। तारीख 23-11-2025 के दिन जामनगर के परमार परिवार की बेटी श्री संजना परमार का विवाह शहर के टाउन हॉल में होना निर्धारित हुआ था। परिवार में शुभ अवसर था, खुशियाँ समा नहीं रही थीं, सभी विधियाँ और तैयारियाँ पूर्णता की ओर थीं। तभी समाचार मिला कि ता. 24-11-2025 के दिन राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जामनगर पधारने वाले हैं। जामनगर के टाउन हॉल में मुख्यमंत्री का सार्वजनिक कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। यह कार्यक्रम श्री संजना परमार के विवाह के ठीक एक दिन बाद होने के कारण आसपास के क्षेत्र में पुलिस बंदोबस्त तथा सुरक्षा व्यवस्थाएँ की गई थीं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के कारण विवाह समारोह में अवरोध उत्पन्न होने की आशंका थी, जिसके चलते परमार परिवार की चिंता बढ़ गई।

परिवार ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया। बात मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँची। बात सुनकर मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा, "हमारे कार्यक्रम का स्थल बदलो। बेटी के परिवार की चिंता हमारी चिंता।" मुख्यमंत्री के आदेश के चलते कार्यक्रम का स्थल बदला गया।

इस घटनाक्रम के विषय में बात करते हुए श्री संजना परमार के काका श्री ब्रिजेश परमार कहते हैं, "मुख्यमंत्री ने हमारे विवाह प्रसंग की जानकारी मिलते ही हमसे बातचीत की और आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'आप जरा भी चिंता मत करना। आपका विवाह प्रसंग जहाँ निर्धारित था, उसी टाउन हॉल में धूमधाम से ही कीजिए। हम हमारे कार्यक्रम का स्थल बदल देंगे।'" इस प्रकार मुख्यमंत्री की इस संवेदना से परमार परिवार की चिंता दूर हुई।

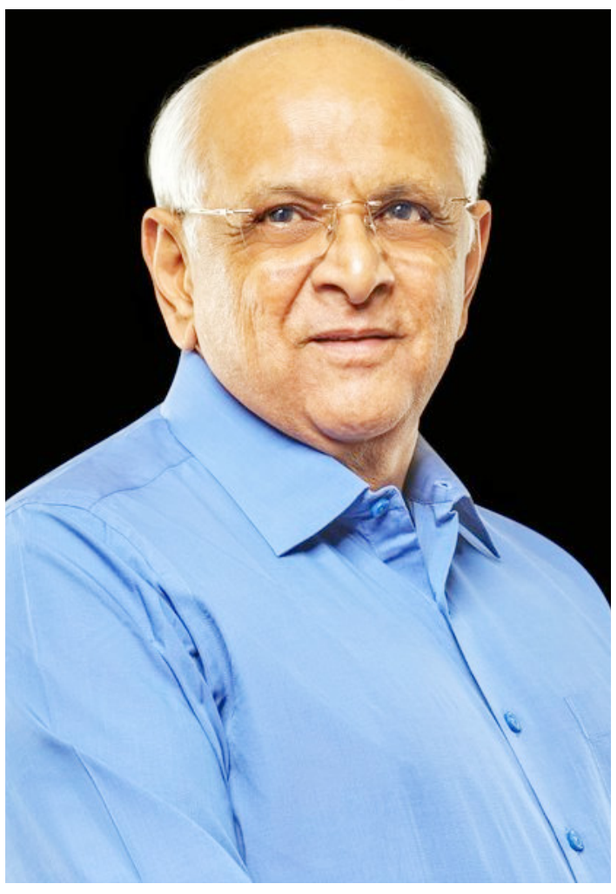

ब्रिजेश परमार मुख्यमंत्री का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं : "विवाह के मौसम में तत्काल नया स्थल खोजना, मेहमानों को सूचित करना, नई व्यवस्थाएँ करना; ये सब हमारे लिए मुश्किल था, परंतु आभार मुख्यमंत्री का, जिन्होंने हमारा प्रसंग शांति एवं सुखपूर्वक आयोजित हो; इसके लिए अपने कार्यक्रम का स्थल बदला। मुख्यमंत्री साहब का एक फोन आया और उस रात हम शांति से सो सके।" यह घटना दर्शाती है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल मृदु एवं दृढ़ मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ ही 'उत्तम इंसान' भी हैं। वे जनता की छोटी से छोटी मुश्किलों के लिए भी सदा संवेदनशील हैं।

बीएलओ की मौतों से उठी लोकतंत्र की चीख—राहुल गांधी का आरोप, 'एसआईआर नहीं, जनता पर थोपा गया ज़ुल्म'

(जीएनएस)। नई दिल्ली की राजनीतिक हवा उस समय अचानक भारी हो गई, जब कांग्रेस ने पूरे देश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न—यानी मतदाता सूची के एसआईआर—को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने एक के बाद एक ऐसे आरोप लगाए जिन्हें पढ़कर देश में मतदाता अधिकार, चुनावी पारदर्शिता और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर तीखी बहस शुरू हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने ऐसा बोझ और ऐसी अफरा-तफरी पैदा कर दी है कि यह सुधार नहीं, बल्कि एक 'थोपा गया ज़ुल्म' बन गया है। उनके शब्दों की गंभीरता तब और बढ़ गई जब उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के कारण बीते उन्नीस दिनों में छह राज्यों के भीतर सोलह बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। राहुल गांधी के हाथ में अख़बार की कटिंग थी, जिसमें बीएलओ की अचानक हुई मौतों की कहानियाँ दर्ज थीं—कहीं दिल का दौरा, कहीं तनाव का भार, कहीं आत्महत्या के प्रश्न और कहीं प्रशासनिक दबाव के बोझ से टूटा हुआ मन। राहुल गांधी ने कहा कि इन मौतों में सिर्फ संयोग नहीं छिपा, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की क्रूरता है जो लाखों पन्नों वाली पुरानी मतदाता सूची लोगों के आगे फेंक देती है और उनसे कहती है कि वे उसमें अपना नाम ढूंढें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने लोगों को डिजिटल सूचियों की जगह 22 साल पुराने स्कैन किए हुए दस्तावेज़ों के ढेरों में धकेलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि सही मतदाता अपनी पहचान खोजते-खोजते थक जाएँ, और 'वोट चोरी' का खेल बिना किसी रोकटोक जारी रहे।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत वह देश है जहाँ विश्व के सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं, लेकिन जब बात चुनाव आयोग की आती है तो तकनीक गायब हो जाती है और उसकी जगह कागजों का एक ऐसा जंगल खड़ा हो जाता है जिसके बीच आम नागरिक अपनी नागरिकता की खोज में खो जाता है। राहुल गांधी ने इस पूरे एसआईआर अभियान को एक सुनियोजित राजनैतिक चाल कहा—ऐसी चाल जिसमें सत्ता को बचाने के लिए लोकतंत्र की नींव को हिलाने में कोई हिचक नहीं दिखाई देती।

राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वर और भी तीखा था। उन्होंने कहा कि एसआईआर की यह अराजक प्रक्रिया उन्हें नोटबंदी के दिनों की हड़बड़ी और कोविड-19 लॉकडाउन की अनियोजित घबराहट की याद दिलाती है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी का 'वोट चोरी' मॉडल अब आम लोगों की जान लेने लगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मृत बीएलओ की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है, और यह सवाल उठाया कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा? खड़गे के मुताबिक यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ एक संगठित हमला है जिसमें संविधान को दरकिनार कर दिया गया है।

इस विवाद में एक और गंभीर मोड़ तब आया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी आवाज़ इस रोष में मिला दी। राज्य के नदिया ज़िले में एक महिला बीएलओ अपने घर में फंदे से लटकी मिली। पुलिस ने कहा कि वह अत्यधिक कार्य दबाव में थी। ममता बनर्जी ने इस घटना को एसआईआर की क्रूरता का प्रत्यक्ष उदाहरण बताते हुए चुनाव आयोग से इस पूरी प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की। उनका कहना था कि यह अभियान अपने उद्देश्य से भटक चुका है और अब यह लोकतंत्र के उन पहियों को कुचलने लगा है जिन पर इस देश की चुनावी व्यवस्था खड़ी है।

देश की राजनीति इन दिनों तीखी बहसों से भर चुकी है, और एसआईआर अब सिर्फ मतदाता सूची का तकनीकी काम नहीं रह गया। यह शासन, संवेदनशीलता, जवाबदेही और चुनावी विश्वास के प्रश्नों के बीच खड़े एक ऐसे बड़े विवाद का चेहरा बन चुका है जिसकी गूंज आने वाले दिनों में और तेज होगी। बीएलओ की मौतें सिर्फ आँकड़े नहीं है—वे इस बात की याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था इंसानों के जीवन को भी उतनी ही गंभीरता से देखे जितनी वोटों की गिनती को। और इन मौतों के बीच राहुल गांधी का यह आरोप, कि एसआईआर सुधार नहीं बल्कि ज़ुल्म है, आने वाले दिनों में राजनीतिक संघर्ष का एक केंद्रीय स्वर बन सकता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सीमावर्ती कच्छ जिले को को एक ही दिन में 680 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भुज शहर से कच्छ जिले के 503 करोड़ रुपए से अधिक के 55 विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ गांधीधाम मनपा के 176 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- कच्छ में उद्योगों और पर्यटन के विकास के कारण स्थानीय रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं
- आगामी जनवरी में राजकोट में आयोजित होने वाली सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र की रीजनल कॉन्फ्रेंस से कच्छ के औद्योगिक निवेश को नया बल मिलेगा
- कच्छ को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए रीजनल इकोनॉमिक प्लान तैयार किया जा रहा है
- कच्छ जिले के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास से शहरों में आंतरिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा सुगम होगी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को भुज शहर के लालन कॉलेज मैदान से सीमावर्ती कच्छ जिले को 503 करोड़ रुपए से अधिक के 55 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 498 करोड़ रुपए के 52 कार्यों का शिलान्यास और 5.79 करोड़ रुपए लागत के 3 कार्यों का लोकार्पण किया।

कच्छ की धरा पर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से कच्छी लोगों के जीवन में आए बदलाव को लेकर कहा कि कच्छी माड़ुओं के जज्बे और पुरुषार्थ से जिले में विकास के नए चमत्कार हुए हैं। प्रधानमंत्री के विजन से कच्छ सबसे तेजी से विकास करने वाला जिला बना है। विनाशक भूकंप के बाद प्रधानमंत्री के विकास के विजन तथा कच्छ के नागरिकों के सहयोग से आज जिले में उद्योग-धंधे, रोजगार और पर्यटन का तेज गति से विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा की पाइपलाइन और नहरों के नेटवर्क से कच्छ के विकास का कायाकल्प हुआ है। कच्छ का रण उत्सव, स्मृति वन और श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल कच्छी संस्कृति के विकास मंदिर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कच्छ का सुनियोजित विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने कच्छ को दोगुनी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। गांधीधाम को महानगर पालिका का दर्जा मिलने से विकास की गति और अधिक तेज होगी।

विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से कच्छ में बढ़ने वाली बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भुज, अंजार, अबडासा, मांडवी और रापर क्षेत्रों को 503 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों से विकास की नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कच्छ जिले के शहरों को जोड़ने वाली आंतरिक सड़कों के मजबूतीकरण और नवीनीकरण से पर्यटन को गति मिलेगी और नागरिकों का आवागमन सुगम होगा। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से जल संचय सहित अन्य कार्यों में सहभागी होने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क आकार ले रहा है, जो गुजरात को रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनाएगा। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से धोरडो रण उत्सव के कारण 'इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन' बना है। धोरडो के सफेद रण को दुनिया के 'बेस्ट टूरिज्म विलेज' की सूची में स्थान मिला है। कच्छ में उद्योगों और पर्यटन विकास के कारण स्थानीय रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वांगीण विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात के हर क्षेत्र के विकास की स्थानीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई है। गुजरात में चार रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। आगामी जनवरी में राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र की रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और इससे कच्छ के औद्योगिक निवेश को नया बल मिलेगा।

विश्वस्तरीय शहरों का निर्माण करने के लिए वर्ष 2047 तक की योजना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के निकट स्थित क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रोथ हब मॉडल लागू किया गया है। कच्छ को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए रीजनल इकोनॉमिक प्लान तैयार किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कच्छ जिले के नागरिकों के जोश की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक तंत्र और नागरिकों के समन्वय की प्रशंसा की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कच्छी लोगों के जज्बे और देश के लिए सर्वस्व समर्पित करने की राष्ट्र प्रथम की भावना को अभिनंदन के पात्र बताया।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प में सहभागी होने तथा 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल फॉर ग्लोबल' के मंत्र को जीवन में आत्मसात कर स्थानीय चीजों की खरीदी करने का अनुरोध किया। उन्होंने नागरिकों से आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत बनाने में आगे रहने की अपील की।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा ने कहा कि आज विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का समारोह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के कच्छ के प्रति विशेष प्रेम एवं भाव का परिचायक है। राज्य मंत्री ने गुजरात सरकार के कौशल वर्धन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दृष्टिकोण को सराहते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के निर्णय से ही कच्छ में शिक्षकों की विशेष भर्ती संभव हो पाई है। कच्छ में शिक्षकों की विशेष भर्ती प्रक्रिया से और 'जहां नौकरी, वहीं सेवानिवृत्ति' के निर्णय से सुदूरवर्ती गांवों तक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। उन्होंने सड़कों आदि सहित ढांचागत सुविधाओं के विकास की गुजरात सरकार की अविरत यात्रा की प्रशंसा की। राज्य मंत्री ने नागरिकों से देश के विकास में तत्परता के साथ सहभागी होने का अनुरोध किया। उन्होंने कच्छ जिले के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

कच्छ-मोरबी के सांसद श्री विनोदभाई चावड़ा ने कहा कि गांधीधाम को मिले महानगर पालिका के दर्जे से इस क्षेत्र में नया परिवर्तन आएगा। उन्होंने कच्छ के अनेक विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री चावड़ा ने कहा कि डबल इंजन सरकार की कच्छ के प्रति निरंतर चिंता के कारण आज कच्छ में पर्यटन, उद्योग और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है।

भुज के विधायक श्री केशुभाई पटेल ने विकास कार्यों की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने कच्छ जिले को विकास के क्षेत्र में अनेक भेंट प्रदान कर अग्रसर रखा है। सरकार ने कच्छ जिले की कई समस्याओं का सुखद समाधान किया है, जिससे कच्छी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कच्छ के विकास का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को दिया और कहा कि कच्छ में सड़कों के विकास से यात्रा और परिवहन सुगम होगा।

कच्छ पधारे मुख्यमंत्री का विभिन्न संगठनों और जिला प्रशासन की टीम ने स्थानीय संस्कृति के अनुसार कच्छी पगड़ी और शॉल भेंट कर स्वागत किया।

उल्लेखनीय है कि कच्छ जिले में आज विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से आंतरिक सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। शिलान्यास कार्यों में भुज शहर की सभी महत्वपूर्ण सड़कों को शामिल किए जाने से शहर के नागरिकों को उत्तम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने सड़क एवं मकान विभाग के 393.39 करोड़ रुपए के 23 कार्यों का शिलान्यास, वन विभाग के 2.60 करोड़ रुपए के छारी ढंढ और पडाला मैंग्रोव लर्निंग सेंटर के विकास कार्य का लोकार्पण, सिंचाई विभाग के 6 करोड़ रुपए के अधिक के खर्च से कच्छ के विभिन्न गांवों में तालाब सुधार के कार्यों का शिलान्यास, शिक्षा विभाग द्वारा कच्छ के गुनेरी में 3.19 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित नए माध्यमिक स्कूल का लोकार्पण, गुजरात राज्य सड़क विकास निगम (जीएसआरडीसी) द्वारा 42.50 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित भुज-मुंद्रा रोड और 19.72 करोड़ रुपए के खर्च से भुज-नखत्राणा रोड के मजबूतीकरण और रिसर्फेसिंग कार्यों के शिलान्यास के साथ ही सड़क एवं भवन पंचायत विभाग के 26.52 करोड़ रुपए के खर्च से प्रस्तावित विभिन्न सड़कों के रिसर्फेसिंग कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जनकसिंह जाडेजा, अबडासा के विधायक श्री प्रद्युम्नसिंह जाडेजा, अग्रणी श्री देवजीभाई वरचंद, भुज नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रश्मिबेन सोलंकी, भुज तहसील पंचायत अध्यक्ष श्री विनोदभाई वरसाणी, कच्छ कलेक्टर श्री आनंद पटेल सहित कई अधिकारी, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

G20 समिट में वैश्विक आतंकवाद पर PM मोदी की निर्णायक चेतावनी: IBSA देशों को संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। G20 समिट का व्यस्त कार्यक्रम उस क्षण थोड़ी देर के लिए ठहर-सा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर एक अत्यंत संवेदनशील विषय—वैश्विक आतंकवाद और बहुपक्षीय सहयोग—पर खुलकर बात की। दुनिया अनेक राजनीतिक तनावों और आर्थिक अस्थिरताओं के बीच जूझ रही है, लेकिन इस मुलाकात का सबसे प्रमुख संदेश था कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में अब किसी तरह की ढिलाई या दोहरे रवैये की गुंजाइश नहीं रह गई है। मोदी ने साफ कहा कि यह पूरी मानवता के लिए अस्तित्व का सवाल बन चुका है और IBSA देशों को मिलकर अपने नैतिक और राजनीतिक दायित्वों को नए संकल्प के साथ निभाना होगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संरचनाएं अभी भी पिछली सदी के मॉडल में अटकी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है, उनकी नजर में अब प्रासंगिकता के संकट से गुजर रही है। मोदी का कहना था कि इस मंच में सुधार केवल जरूरी ही नहीं, बल्कि तत्काल आवश्यक है, और IBSA देशों को अपने साझा अनुभव व समान लोकतांत्रिक मूल्य देखते हुए इस मुद्दे पर एक तीखे और स्पष्ट स्वर में दुनिया को संदेश देना चाहिए। उन्होंने यह विचार भी रखा कि आज जब दुनिया क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, युद्धों और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बिखरती दिख रही है, तब IBSA जैसे प्लेटफॉर्म सहयोग और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली आशा की आवाज़ बन सकते हैं।

बैठक में मोदी ने IBSA की उस भूमिका पर भी जोर दिया जो वह आधुनिक तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु-लचीली कृषि के क्षेत्र में निभा सकता है। IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस और क्लाइमेट-रेसिलिएंट एग्रीकल्चर फंड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह तीनों महाद्वीपों में फैला यह समूह वैश्विक दक्षिण के लिए वास्तविक समाधान तैयार कर सकता है—ऐसे समाधान जो न सिर्फ तकनीकी हों, बल्कि मानवीय भी हों। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में IBSA फंड के जरिए दुनिया के 40 देशों में 50 से अधिक परियोजनाएं पहले ही लागू हो चुकी हैं। इससे स्पष्ट है कि यह मंच केवल राजनीतिक संवाद का स्थल नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव का वास्तविक माध्यम भी बन चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि और स्वास्थ्य के पारंपरिक ज्ञान से लेकर हरित ऊर्जा और मिलेट्स तक—विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि अगर IBSA अपने संयुक्त अनुभवों और संसाधनों को एक साझा दृष्टिकोण में बदल दे, तो यह न केवल वैश्विक दक्षिण बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। उनकी बातों में एक ऐसे नेतृत्व की स्पष्टता थी, जो समझता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यवहारिक यथार्थ है। इस मुलाकात का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि दुनिया के बड़े मंचों पर अक्सर राजनीतिक मतभेद प्रगति को रोक देते हैं। लेकिन IBSA, अपनी विविधता के बावजूद, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय जैसे साझा आदर्शों पर खड़ा है। मोदी की यह अपील कि आतंकवाद के खिलाफ एक समान नीति अपनाई जाए और सुरक्षा सलाहकार स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित हों, इस समूह को और अधिक संगठित बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

G20 समिट के शोर-शराबे और कूटनीतिक व्यस्तताओं के बीच IBSA की यह बैठक जैसे दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे रही थी—कि जब बड़े महाद्वीपों की तीन उभरती शक्तियां अपनी आवाज़ मिलाती हैं, तो वैश्विक व्यवस्था में बदलाव केवल एक संभावना नहीं, बल्कि एक निकट भविष्य बन जाता है। और इसी भविष्य की दिशा में यह बातचीत, यह चेतावनी और यह संकल्प एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज हो सकता है।

हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश—जांच एजेंसियों को नहीं मिला बैंकों के खाते 'डेबिट फ्रीज' करने का अधिकार, नागरिकों को मिली बड़ी राहत

(जीएनएस)। नागपुर की अदालत से निकला यह फैसला उन लाखों नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो साइबर धोखाधड़ी या अन्य विवादित मामलों में बिना पूर्व सूचना के अपने ही बैंक खातों को अचानक बंद या डेबिट फ्रीज होते देखते हैं। नागपुर हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 106 किसी भी जांच एजेंसी को बैंक खाते को न तो अटैच करने का अधिकार देती है और न ही उस खाते को 'डेबिट फ्रीज' करने का। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक महत्वपूर्ण फौजदारी रिट याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उनके खाते साइबर धोखाधड़ी के नाम पर बिना किसी वैधानिक आदेश के फ्रीज कर दिए गए।

न्यायमूर्ति अनिल पानसरे और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ ने पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की और पाया कि जांच एजेंसी ने जिस धारा 106 पर भरोसा किया था, वह सिर्फ यह अनुमति देती है कि संदिग्ध संपत्ति या धनराशि पर अस्थायी रोक तभी लगाई जा सकती है, जब सक्षम प्राधिकारी एक स्पष्ट, लिखित आदेश जारी करे। लेकिन इस मामले में न तो ऐसा कोई आदेश मौजूद था और न ही बैंकों को वह पत्र भेजा गया था जिसके आधार पर वे खाते फ्रीज करते। कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को 'रहस्यपूर्ण' बताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया न्याय और कानूनी शुचिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है।

याचिकाकर्ता कार्तिक चतुर और अन्य लोगों ने बताया कि कथित साइबर धोखाधड़ी की रकम का हवाला देकर उनके बैंक खातों को अचानक डेबिट फ्रीज कर दिया गया। जब उन्होंने बैंक से पूछा कि किस प्राधिकारी ने आदेश जारी किया है, तो बैंक के पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। जाँच में यह बात सामने आई कि कई मामलों में बैंक ने सिर्फ मौखिक सूचना या अनौपचारिक संकेत के आधार पर खाते रोक दिए थे, जो कानून के किसी भी मानक पर स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि BNSS के प्रावधानों का यही इस्तेमाल होता रहा, तो नागरिकों का वित्तीय स्वतंत्रता का वैधानिक अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होगा।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह भी रास्ता दिखाया कि वे इस अवैध कार्रवाई के खिलाफ उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाकर मुआवजे की मांग कर सकते हैं। अदालत ने केरल हाई कोर्ट के प्रसिद्ध फैसले "हेडस्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य" का हवाला देते हुए कहा कि वह निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट की मूक स्वीकृति के साथ प्रभावी मिसाल बन चुका है, और किसी भी जांच एजेंसी द्वारा खातों को मनमाने ढंग से फ्रीज करने की प्रवृत्ति न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं सकती।

इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह निर्देश है जो अदालत ने बैंकों को दिया। अदालत ने साफ कहा कि हर बैंक, भुगतान इंटरमीडियरी और वित्तीय संस्था को गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारा निर्धारित "Citizen Financial Cyber Frauds Reporting and Management System" के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी खाते से धोखाधड़ी की राशि जुड़ी हुई है, तो बैंक सिर्फ विवादित रकम को होल्ड कर सकता है, पर पूरे खाते को डेबिट फ्रीज नहीं कर सकता—जब तक कि कोई सक्षम, लिखित, कानूनी आदेश न मिले। नागपुर हाई कोर्ट का यह फैसला एक ऐसे समय में आया है जब देश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और जांच एजेंसियाँ अक्सर संदेह के आधार पर खातों को रोक देती हैं। यह निर्णय बैंकिंग व्यवस्था, आम नागरिकों और वित्तीय अधिकारों की सुरक्षा के बीच एक नया संतुलन स्थापित करता है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जांच एजेंसियों को अपनी शक्ति का उपयोग 'अनुमान' या 'संकेत' के आधार पर नहीं, बल्कि कानून की सीमा में रहते हुए करना होगा। यह फैसला आने वाले वर्षों में देश भर में बैंकिंग और साइबर क्राइम जांच की पद्धति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है—क्योंकि न्यायपालिका ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बिना अधिकार के की गई कार्रवाई सिर्फ अवैध नहीं, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता का सीधा हनन है।

प्रेम ने लिया हिंसक मोड़-प्रेमिका के इनकार से बौखलाए युवक ने उसके भाई की हत्या की, पुलिस ने कुछ घंटों में आरोपी को पकड़ा

(जीएनएस)। अहमदाबाद शहर की रात शनिवार को उस समय दहल उठी, जब वटवा जीआईडीसी थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध से जुड़ा एक मामला अचानक खून-खराबे में बदल गया। त्रिकमपुरा केनाल पुल के सन्नाटे में हुई इस वारदात ने न सिर्फ एक परिवार को शोक में डुबो दिया, बल्कि इस शहर को फिर याद दिलाया कि जुनूनी प्रेम कभी-कभी कितनी भयानक दिशा ले सकता है। जिस युवक को एक युवती के साथ भविष्य बसाने का सपना था, उसी प्रेम की सनक में उसने युवती के मासूम भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। और यह सब कुछ उस समय हुआ, जब युवती ने संबंध से कदम पीछे खींच लिया और बातचीत करने से इनकार कर दिया।

पुलिस के अनुसार मृतक मनीष सुथार, 23 वर्ष, मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले की बालोतरा तहसील के एक गांव का निवासी था और अहमदाबाद में परिवार के साथ प्लास्टिक के व्यापार से जुड़ा था। शनिवार देर रात लगभग 11 बजे के आसपास, वह त्रिकमपुरा केनाल पुल के किनारे झुग्गी क्षेत्र के पास आरोपी अश्विन झाला से मिलने गया था। मनीष का उद्देश्य था अश्विन को समझाना, उसे शांत करना और उसकी बहन से दूरी बनाए रखने के लिए समझदारी से बातचीत करना। पर मनीष को अंदाज़ा नहीं था कि जिस युवक को वह समझाने जा रहा है, उसके भीतर अस्वीकार किए जाने का जो ज्वालामुखी उबल रहा था, वह किसी भी क्षण फट सकता है।

तीन साल पहले, नवरात्रि के दौरान नारोल क्षेत्र में अश्विन और युवती का परिचय हुआ था। धीरे-धीरे यह परिचय प्रेम संबंध में बदल गया। लेकिन जब परिवार को इस रिश्ते का पता चला, तो उन्होंने नारोल से घर बदलकर हाथीजण क्षेत्र में आकर बसना ही बेहतर समझा। युवती ने भी परिस्थितियों को देखते हुए अश्विन से दूरी बना ली। बातचीत बंद हो गई। पर अश्विन के लिए यह विराम नहीं, बल्कि चोट बन गया। वह लगातार युवती के पीछे पड़ा रहा, फोन कॉल, पीछा, रास्ता रोकना—सब उसकी आदत का हिस्सा बन गया।

22 नवंबर की रात घटनाओं ने तेज़ मोड़ लिया। युवती अपनी बहन और सहेली के साथ हाथीजण क्षेत्र में एसपी रिंग रोड की सर्विस रोड पर टहल रही थी। अचानक अश्विन वहां

बाइक से पहुंच गया और बिना एक शब्द कहे उनका पीछा करता हुआ घर तक पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद उसने युवती को फोन कर पूछा कि वह उससे बात क्यों नहीं करती और उसने शादी से इनकार क्यों किया। युवती ने साफ शब्दों में कहा कि वह शादी नहीं करना चाहती। फोन काट दिया। लेकिन अश्विन ने फोन पर धमकी के स्वर में कहा कि उसे तुरंत उससे मिलना होगा। दूसरी ओर, युवती अपने भाई मनीष से लगातार बात कर रही थी। उसने मनीष को बताया कि अश्विन फिर उसके आसपास मंडरा रहा है और उसे मिलने के लिए कह रहा है। मनीष ने तुरंत फैसला लिया कि वह अश्विन से बात करेगा, उसे समझाएगा कि उसकी बहन को परेशान करना बंद करे। इसी उद्देश्य से वह रात करीब 11 बजे त्रिकमपुरा केनाल पुल पर पहुंचा, जहां अश्विन पहले से मौजूद था।

लेकिन जो बातचीत शांतिपूर्वक होनी थी, वह क्रोध में बदल गई। पुलिस की शुरुआती जांच बताती है कि अश्विन युवती के इनकार से बुरी तरह आहत था, उस पर जुनूनी आग्रह हावी था, और वह किसी भी साधारण समझाने-बुझाने वाली बात सुनने की स्थिति में नहीं था। इसी तनाव में उसने तीक्ष्ण हथियार निकाला और मनीष के चेहरे, गले और सीने पर कई वार कर दिए। हमले की तीव्रता ऐसी थी कि मनीष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

रात में कुछ समय बाद जब वटवा जीआईडीसी पुलिस टीम युवती के घर पहुंची और परिवार को मनीष की हत्या की खबर दी, तो पूरा घर चीखों और टूटने की आवाज़ों से भर गया। युवती उस समय तक यह उम्मीद कर रही थी कि मनीष बस थोड़ी देर में वापस आएगा। उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि एक गलत वक्त पर हुई मुलाकात उसके भाई को हमेशा के लिए उससे छीन लेगी।

लेकिन इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई। जोन-6 डीसीपी की एलसीबी टीम और स्थानीय वटवा जीआईडीसी थाने की पुलिस ने घटनास्थल, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय इनपुट के आधार पर कुछ ही घंटों में आरोपी अश्विन झाला को हिरासत में ले लिया। रविवार को युवती ने खुद थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

इस पूरी घटना ने एक बार फिर उस दर्दनाक सच्चाई को उजागर किया है कि प्रेम में अस्वीकार का सामना करने की परिपक्वता की कमी, जुनून का विष और एकतरफा मोह का अंधापन किस हद तक हिंसक हो सकता है। एक बहन ने अपना भाई खो दिया, एक परिवार ने अपना युवा बेटा, और एक शहर ने एक और दुखद कहानी दर्ज की—जिसका अंत सिर्फ खून और पछतावे के रूप में लिखा गया।

नवनिर्मित एमएलए आवास और जेपी गंगा पथ पर नीतीश कुमार का दौरा, पटना के विकास को नई गति देने की कोशिश

(जीएनएस)। पटना की ठंडी सुबह में रविवार का सूरज धीरे-धीरे ऊपर उठ ही रहा था कि दारोगा राय पथ स्थित नवनिर्मित एमएलए डुप्लेक्स आवास परिसर में हलचल बढ़ गई। सुरक्षा बलों की मध्यम गति वाली हलचल, अधिकारियों के बीच संवाद, और परिसर में खड़े चमचमाते नये आवासों के बीच एक इंतज़ार था—बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। थोड़ी देर बाद उनका काफिला वहाँ पहुँचा और उसी क्षण माहौल में एक औपचारिक सक्रियता आ गई। मुख्यमंत्री ने उतरते ही पूरे परिसर को ध्यान से देखना शुरू किया, मानो वे केवल निरीक्षण नहीं बल्कि उस भविष्य को देख रहे हों जिसमें ये आवास आने वाले विधायकों के रहने-सहने की नई पहचान बनने वाले हैं।

मुख्यमंत्री धीरे-धीरे प्रत्येक आवास के सामने रुकते, उसकी संरचना, उसकी बनावट, और दी गई सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेते रहे। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हर आवास पर उसके अनुरूप निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र साफ-साफ अंकित किया गया है, जिससे आवंटन और पहचान में किसी तरह की दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री ने आवासों की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये आवास बेहद अच्छी तरह तैयार किए गए हैं और इन्हें जल्द ही नवनिर्वाचित विधायकों को उनके क्षेत्रों के आधार पर आवंटित कर दिया जाएगा। उनकी आवाज़ में संतुष्टि का भाव साफ झलक रहा था, जैसे यह परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि विधायकों के सुगम निवास की दिशा में एक मजबूत कदम हो।

इस पूरे परिसर में आधुनिक सुविधाओं और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कहीं रंगों की झलक थी, तो कहीं संयोजन में प्रशासनिक अनुशासन का प्रभाव। मुख्यमंत्री ने वहाँ उपस्थित अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि यह परिसर आने वाले समय में विधायकों के कामकाज और जीवन को सरल बनाएगा। निरीक्षण के दौरान उनकी नज़र किसी एक बिंदु पर नहीं ठहरती थी—वे दीवारों पर लगे नंबर, फुटपाथ की गुणवत्ता, हरियाली के लिए की गई सजावट, प्रकाश व्यवस्था और आवासों के अंदर की संरचना—सब पर बराबर ध्यान दे रहे थे।

एमएलए आवास का निरीक्षण पूरा होते ही मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ जेपी गंगा पथ की ओर बढ़े। जैसे ही गंगा किनारे बनी इस आधुनिक पथ पर पहुंचे, हवा में मौजूद नमी और दूर तक फैली गंगा की चमक ने वातावरण को प्राकृतिक सुंदरता से भर दिया। मुख्यमंत्री ने वहाँ चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य को ध्यान से देखा। पथ के किनारे बन रहे पार्क, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा के लिए प्रस्तावित रेलिंग, और सड़कों के किनारों के रखरखाव—इन सभी पर उन्होंने अलग-अलग अधिकारियों से विस्तार से सवाल किए और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। जेपी गंगा पथ को पटना शहर के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन माना जाता है। इससे न केवल आवागमन सरल हुआ है, बल्कि शहर को एक ऐसा तटीय सौंदर्य भी मिला है जो पहले कभी इस रूप में सामने नहीं आया था।

भारत से दक्षिण अफ्रीका तक रेल कूटनीति की नई छलांग, राइट्स पहली बार चालू हालत वाले डीज़ल लोकोमोटिव भेजने को तैयार

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सुबह में जब रेल मंत्रालय की इमारतों के भीतर बैठकें और फाइलों की आवाजाही अपने सामान्य क्रम में चल रही थी, तभी एक घोषणा ने भारतीय रेल इंजीनियरिंग की लंबे समय से चली आ रही क्षमताओं को एक नए अध्याय में प्रवेश दिला दिया। रेल मंत्रालय के तहत कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राइट्स लिमिटेड ने बताया कि वह पहली बार देश में उपयोग किए जा रहे चालू हालत (वर्किंग कंडीशन) वाले डीज़ल लोकोमोटिव का निर्यात करने जा रही है। यह सिर्फ एक व्यावसायिक सौदा नहीं, बल्कि भारतीय रेल प्रौद्योगिकी की वैश्विक यात्रा का वह मोड़ है जहाँ पुराने संसाधनों को नए रूप में इस्तेमाल करते हुए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को एक नई दिशा दी जा रही है।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा 18 डीज़ल लोकोमोटिव का दिया गया यह ऑर्डर दोनों देशों के बीच रेल सहयोग को एक मजबूत आधार देता है। राइट्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राहुल मिथल ने बताया कि भारत का रेल नेटवर्क लगभग पूरी तरह विद्युतीकृत हो चुका है। ऐसे में वे डीज़ल इंजन, जिनकी शेष आयु 15 वर्ष से अधिक है और जो अभी भी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, उन्हें विदेशों में उपयोग किए जाने की संभावना तलाशना एक स्वाभाविक कदम बन गया है। यह निर्णय न केवल संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण है, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग के प्रति बढ़ते विश्वास का भी संकेत है। राहुल मिथल ने विस्तार से बताया कि अब तक राइट्स केवल नए लोकोमोटिव का ही निर्यात करती रही है, लेकिन यह पहली बार है जब चालू हालत वाले इंजनों को विदेश भेजने की तैयारी की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका का रेल गेज केप गेज (1,067 मिमी) है, जबकि भारत में ब्रॉड गेज (1,676 मिमी) उपयोग होता है। इन दोनों के बीच तकनीकी अंतर कई बार एक बड़ी चुनौती बनता है, लेकिन भारतीय इंजीनियरिंग की तकनीकी दक्षता और राइट्स के अनुभव ने इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदल दिया है। संशोधन कार्य के बाद ये इंजन दक्षिण अफ्रीकी रेल नेटवर्क के लिए पूर्णतः अनुकूल हो जाएंगे।

दक्षिण अफ्रीका के लिए यह सौदा केवल खरीद का मामला नहीं है, बल्कि रेलवे प्रणाली की मजबूती और उनकी आवश्यकता के अनुसार विश्वसनीय इंजन प्राप्त करने का भरोसा भी है। भारत से निर्यात किए जाने वाले ये लोकोमोटिव उनकी माल ढुलाई और लंबी दूरी के परिचालन में नई ऊर्जा भरने वाले हैं।

राहुल मिथल के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 की चौथी तिमाही तक पहला संशोधित लोकोमोटिव दक्षिण अफ्रीका को भेज दिया जाएगा। इस समय-सीमा का पालन करने के लिए राइट्स की विभिन्न टीमें निरंतर काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि दक्षिण अफ्रीका इन इंजनों की गुणवत्ता और प्रदर्शन से संतुष्ट होता है, तो पड़ोसी देशों—जैसे बोत्सवाना, जाम्बिया, नामीबिया—से भी ऐसे ही ऑर्डर मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि एक निर्यात श्रृंखला की शुरुआत है, जो भारत की तकनीकी क्षमता को अफ्रीकी महाद्वीप में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित कर सकती है।